following amendment be made in the Finance (No. 2) Bill, 1991, as passed by the Lok Sabha, namely:—

'That at page 66 for lines 14 to 21 the following be *substituted*, namely:—

(i) where the total income does not exceed Rs. 50,000—Nil.'"

34. "That the Rajya Sabha recommendations to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Finance (No. 2) Bill, 1991 as passed by the Lok Sabha, namely:—

'That at page 73 for lines 29 to 36 the following be *substituted*, namely:—

'Where the total income does not exceed Rs. 50,000 Nil'"—

The questions were put and the motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The question is:

"That the First Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule, The Third Schedule, The Fourth Schedule and The Fifth Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MANMOHAN SINGH: I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, we take up The Voluntary Deposits (Immunities and Exemptions) Bill, 1991. The question is:

"That the Bill to provide for certain immunities to persons making voluntary deposits with the National Housing Bank and for certain exemptions from direct taxes in relation to such deposits and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is one announcement. Looking to the agenda before us, there will be a dinner time. Dinner will be available to all those who want it at 8 P.M. in room No. 70.

Second announcement is, regarding abduction of five diamond merchants raised in this House, Hon. Minister will make a statement after we finish with other subjects.

THE JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION (NO 3) BILL, 1991

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain

sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, The Jammu and Kashmir Appropriation (No. 3) Bill, 1991, authorises payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha. This includes a sum of Rs. 2216.53 crores voted by Lok Sabha on 14th September 1991 and Rs. 492.98 crores charged from the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir. These amounts inclusive of the amounts authorised for withdrawal under the Jamm and Kashmir Appropriation (Vote on Account) Act, 1991 have been sought to enable the Government of Jammu and Kashmir to meet the expenditure during the current financial year.

Sir, I move the Bill for consideration of the House.

The question was proposed.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, जनाबे आली कभी-कभी इन्सान की कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि न चाहते हुए भी किसी बात की ताईद करनी पड़ती है । इसी हालत में हमें मजबूरन काश्मीर के बजट की ताईद सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि जब जम्मू एण्ड काश्मीर में रियासते असेम्बली नहीं है तो जाहिर है कि कानूनन इस पार्लियामेंट को काश्मीर का बजट पास करना होगा । लेकिन बारहा ऐसी हालत की जरूरत क्यों पेश आती है । इसलिए जितनी जल्दी हो सके काश्मीर में इलेक्शन करवाकर इस काम को वहां की रियासते असेम्बली के हवाले कर देना चाहिए । कानून के एहतराम और काश्मीरी अवाम की जरूरतों के पेशे नजर बजट तो हमें पास करवाना हीं है, मगर मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि हुकूमते हिंद कहती है कि काश्मीर में इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं हैं । लेकिन मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आसाम गण परिषद् की मुन्तखब हुकूमत को चन्द्रशेखर सरकार बर्खास्त कर रही थी तो उसने "उल्फा" आतंकवादियों को खास वजह करार दिया था और साफ लफ्जों में चन्द्रशेखर सरकार ने कहा था कि आसाम की हालात काश्मीर से भी ज्यादा बदतर और खराब हो चुके हैं । लेकिन इसके बावजूद वहां आसाम में असेम्बली का इलेक्शन करवाये गये और आसाम में रियासते हुकूमत कायम हो गयी । इसलिए कोई वजह नजर नहीं आती कि जब हुकूमत के कहने के मुताबिक काश्मीर से ज्यादा खराब हालत आसाम में है तो फिर काश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते हैं । मेरे लिए तो बहुत ताज्जुब की बात है । बार-बार काश्मीरी अवाम को हके रायदहन्दगी से महरूम रखना क्या उनके जम्हूरी हुकूक के साथ मजाक नहीं है । इलेक्शन न करवाने के कारण काश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें हैं, मेरे ख्याल से उनके हाथ मजबूत होते हैं और वे काश्मीर के सदालोह अवाम को यह कहकर गुमराह करते हैं कि काश्मीरी अवाम हिंदुस्तान से अलग हटकर एक इकाई है जिनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और इस तरह वे लोग मुल्क की वहदत के लिए खतरा बन चुके हैं । काश्मीरी अवाम भोले भाले होने के नाते उनकी बातों में भी आते हैं । आज के मखसूस अलगाववादी हालात में अगर रियासते जम्मू काश्मीर में उनकी अपनी हुकूमत होती और मरकज में भी उनके नुमाइंदे होते तो उनको हर तरह से कौमी धारा में जोड़ने में हमें आसानियां मिलतीं ।

जनाबे आली, आपको मालूम है कि अमेरिका की आजादी की लड़ाई की शुरुआत जिस नारे से हुई थी वह नारा यह था कि "नुमाइंदगी नहीं तो टैक्स नहीं" । क्या आप काश्मीर के अलगाववादियों को भी यह नारा देना चाहते हैं कि जिस पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी

नहीं उस हुकूमत के लिए उनकी तरफ से कोई टैक्स नहीं । यह बात बहुत ही खतरनाक है । वहां के आम अवाम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मुहब्बत करते हैं और तकसीमे वतन के मौके पर भी आपने देखा कि काश्मीरी अवाम ने हिंदुस्तान के साथ लड़ने में अपनी एक तारीख बनाई थी । इसलिए मुल्क की सालमियत और कौमी एकता के लिए नीज काश्मीरियों की भलाई के लिए जितना जल्द मुमकिन हो इलेक्शन करवा देना ही बेहतर होगा । हम उम्मीद करते हैं कि काश्मीर का अगला बजट उनकी अपनी असेम्बली में पास होगा और तमाम पार्टियां कौमी मफाद में इसका ताउन भी करेंगी ।

जनाबे मन, जम्हूरी मुल्क और जम्हूरियत में बजट का मतलब जो हमने समझा है वह यह है कि अवामी जज्बात और ख्वाहिशात का भी बजट के जरिये इजहार होता है और अवामी जिंदगी की मादी जरूरियात की तकमीन भी बजट के जरिये होती है । इसलिए बजट पर बहस और मबाहिसा हमारे यहां भी होता रहता है जहां अवाम के नुमाइन्दे अपनी इलाकाई जरूरतें और मसायल को हाउस में पेश करते रहते हैं । पूरे मुल्क और मुल्क के हर इलाके के छोटे बड़े मसायल की एक तस्वीर पार्लियामेंट के अंदर उभरती है और बजट अपने लम्बे बाजुओं में तमाम मसायल को समेटकर उसके हल की एक तस्वीर पेश कर देता है।

लेकिन जिस रियासत में असेंबली नहीं होती है उसका बजट नौकरशाही तैयार करती है और हम जो इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और यह जो काश्मीर का बजट हम पास कर रहे हैं इस पर भी उस इलाके के मसायल को देखने वाली न काश्मीरी असेंबली के मैम्बरों की निगाह है और न काश्मीर से चुनकर आने वाले मैंबरान-ए-पार्लियामेंट की निगाह है । एक सत्तारिया साहब को छोड़कर लोक सभा या राज्य सभा में कोई भी काश्मीर का नुमायंदा नहीं है जो वहां के मसायल के पसमंजर में इस बजट पर इजहार-ए-ख्याल करे । मालिक हैं आप जो चाहे पास करवा लें और करवा दें, हम नेक व बद हजूर को समझाए जायेंगे, मानों न मानों जाने जहां अख्तियार है।

जनाब, मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर में जो हालात हैं, इन हालात ने हमारे पूरे मुल्क को मुतफक्किर कर रखा है । काश्मीर के लिए बेपनाह दौलत भी हम शुरू से ही खर्च करते चले आ रहे हैं, "मगर मरीजे इशक पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की" हमने जितना ज्यादा तामीरी अंदाज से काश्मीर के बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा तखरीबी कार्यवाहियां भी हमें देखने को मिलीं । काश्मीर में हमने चाहा था कि गुरबत के माहौल से काश्मीरी अवाम को निकाला जाए, मगर आज भी काश्मीरी अवाम फाकाकशी का शिकार है । काश्मीर में हमने चाहा था कि तालीम को आगे बढ़ाया जाए, मगर आज भी वहां के नौजवान तालीम से बेबहरा दिखलाई देते हैं । काश्मीर के लिए मरकजी हकूमत बेपनाह रुपये-पैसे खर्च करती है । मगर ये रुपये-पैसे न उन लोगों की गुरबत को अब तक दूर कर सके, न उनके अन्दर तालीम, तामीर और तरक्की का ही कोई जजबा पैदा किया जा सका । हमें अपनी उन कमजोरियों को खंगालना होगा, हमें अपनी उन कमजोरियों पर निगाह रखना होगा, जिन कमजोरियों के तहत काश्मीर के मसायल अब तक हम हल करने में मायूस और महरूम दिखलाई देते हैं । आज पाकिस्तान की सरजमीन से काश्मीरी अवाम को गुमराह करने के लिए और काश्मीर को हड़प करने के लिए जिस तरह की साजिशें हो रही हैं वह सारी साजिशें बेनकाब होकर पूरी दुनिया के प्रैस में और पूरी दुनिया के माहौल में आ चुकी हैं । जब हमारी ही सरहद पर एक ऐसा मुल्क बैठा हुआ है जो किसी भी शकल में हमारे मुल्क के तामीर व तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और काश्मीर को हमारे लिए एक

[मौलाना अबदुल्ला खान आजमी]

मुतनाजा फीह मसला बनाकर आए दिन हमें उलझाए रखता है, ऐसी सूरत में हमारी हकूमत को यह चाहिए कि निहायत ही नाजुक तरीन सोच के साथ काश्मीर के मसायल का मुस्तकिल कोई हल निकाले । जिस सूबे में भी, जनाब, अवाम की हकूमत होती है उस सूबे में अवाम अपने सूबे की अलाई के लिए अपनी असेंबली में अपनी सरकार से लड़-झगड़ कर अपने सूबे के हसीन ख्वाब को शर्मिंद-एताबीर करवाते हैं । आज हम जो बजट पास करने जा रहे हैं जाहिर है कि यह बजट हमारा यकीन की बुनियाद पर नहीं, कियाफे और ख्याल की बुनियाद पर पास होने जा रहा है । अगर असेंबली होतीं वहां एम०एल०एज० चुनकर आते, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ होता, वहां से अवामी नमाइंदे आते तो आज वह बतलाते कि काश्मीर के किस जिले में, काश्मीर के किस खित्ते में, काश्मीर के किस हिस्से में, काश्मीर की किस बिरादरी में, काश्मीर के किस खानदान में क्या-क्या तकलीफें और क्या-क्या मुसीबतें मौजूद हैं । मगर उनकी मुसीबतों को खत्म करने के लिए हम इस तरह से बजट पेश करने जा रहे हैं जिस तरह कोई आदमी अटकल और कयास और वहम के साथ हवा और फिजा में कोई तीर चला दे । किसी भी जम्हूरी मुल्क में यह निहायत ही जरूरी है कि उस मुल्क के अवाम को उनका जम्हूरी हक राय दहंदगी दे दिया जाए । जहां-जहां भी जिस-जिस सूबे में इलेक्शन नहीं होते हैं उन सूबों से नफरतों के बादल उठते हैं और वहशतों का पानी बरसता है, इंसानियत की खेत में काल पड़ जाता है । वह काश्मीर जो फूलों की वादी कहलाता है, वह काश्मीर जिसमें जूही और बेला उगते हैं, वह काश्मीर जो अपने दाम में सोसन और यास्मन रखता है, वह काश्मीर जो गुलशन बना हुआ है, वह काश्मीर जिसके लिए शाहजहां ने

7.00 P.M.

कहा था कि, "अगर जन्नत कहीं होती जमीं पर, यहीं होती यहीं होती, यहीं पर ।" ऐसा जन्नते बेनजीर काश्मीर आज जहन्नुम की जमीं पेश कर रहा है। वह काश्मीर यहां से मोहब्बत के बादल उठते थे और प्यार की शबनम बरसा करती थी, आज वहां से नफरत के बादल उठते हैं और खून का पानी बरस रहा है । वह लहू-लूहान काश्मीर आज रो रहा है अपनी किस्मत पर । भारत माता के फरजंदों के अंदर यह एहसास पैदा होना चाहिए कि जितने जल्दी हो सके हम वहां की उस कमी को दूर कर दें जिस कमी की वजह से शको-शुबहात के बादल उठते रहते हैं और हम अपने मुल्क की इज्जतोसलामी के लिए मुस्तकिलन् खतरा पाते हैं ।

काश्मीर की खूबसूरती के सिलसिले में बिरादरेगरामी जनाब बेकल उत्साही एम० पी० जो इसी हाऊस के मुअज्जज मेंबर हैं, उन्होंने अपनी नज्म का एक बंद पेश किया है जिसे मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं । बेकल साहब की शख्सियत और उनकी शायराना अज्मत गैर-ममालिक में भी हिन्दुस्तानी अवाम की अज्मत का इजहार बनती है, जो अपने इस देश में बहतरीन शायर की हैसियत से उभरे हैं और कौमी शायर की हैसियत से जाने-पहचाने जाते हैं । मैं हाउस के लोगों की तबज्जो चाहूंगा । उन्होंने काश्मीर का नक्शा किस तरह खींचा है, आप उसे सामने रखें--

"जिस सरजमीं पर लालों गुल की बहार थी,
जिस खुल्द में थी हसीनो मोहब्बत की बारिशें,
झरनों की लय पर गाती हुई चलती थी हवा,
आज नफरत की लय पर गाती हुई हवा चल रही है।"

शायर के नाजुक ख्याल को देखिए और काश्मीर की वादी में खिलने वाले उन गुल बूटों की नजाकत को महसूस कीजिए जिनसे हमें मोहब्बत की खुशबू मिलती थी और सारा जहां आकर काश्मीर के फूलों की खुशबू में अपने मौसमे जां को मुअत्तर कर के जाता था । कहते हैं कि—

झरनों की लय पर गाती हुई चलती थी हवा,
रंगे चिनार में थी वहीं मौसमों की आग

केसर की बू में हिंद के इतिहास का सुरूर,
उस सरजमीं पर आज है बारूद का गुरूर,
अलगाववाद, खून-खराबा का जोर है,
इंसानियत सिसकती है, जेहलुम का जोर है,
डल झील में अब बर्फ नहीं सिर्फ खून है,
डल झील में अब बर्फ नहीं सिर्फ खून है,
सरकार ही बताए, ये कैसा जनून है ।"

इस जुनून को खत्म करने के लिए मैं अपनी हुकुमत से ये डिमांड करता हूं, कि जितने जल्दी हो काश्मीर की आवाम के हक के लिए रहंदगी को बहाल किया जाए, वहां इलैक्शन करवाए जाएं । इलैक्शन ही वहां थी मसाइल्स का हल होगा । वहां की नुमाइंदा सरकार आएगी। वह अपना बजट पेश करेगी, अपने आवाम की जरूरतों का ख्याल रखेगी । मरकजी हुकूमत, अगर वहां की हुकुमत के पेशकरदा बजट के बाद भी वहां के लोगों की समस्याओं और परेशानियों को महसूस करती है तो मरकजी हुकूमत को आगे बढ़कर उनके हाथ मजबूत करने चाहिए । मैं उम्मीद करता हूं कि और इसी उम्मीद के साथ इस बिल की ताईद कर रहा हूं, इस बजट की मंजूरी की ताईद कर रहा हूं कि अब आगे जो बजट आएगा वह हमारी पार्लियामेंट में नहीं आएगा बल्कि काश्मीर की रियासती एसेंबली में बजट आएगा ताकि लोगों के हक महफूज हो जाएं । याद रखिए अगर हकदार को उसका हक नहीं मिला तो खून की लहरे कभी खामोश नहीं हो सकती । याद रखिए, अगर हकदार को उसका हक नहीं मिला तो नफरत के बादल कभी नहीं हट सकते । हजरत पैगम्बर मुहम्मद सललल्लाहु अलयहे वसल्लम ने इंसानियत को बचाने के लिए एक बड़ा अच्छा आदर्श दिया था । उन्होंने कहा था, "कुल्लाफातिन जी हकिकन हक्का।" ऐ लोगों अगर दुनिया में अमन चाहते हो, चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो तो हर हकदार का हक उसको दे दो । आज सारी दुनिया में लडाई सिर्फ हक की हो रही है । काश्मीर बंद, आसाम बंद, बंबई बंद, कलकत्ता बंद,— ये जो बंद के नारे लगते हैं, बाद में पार्टियां भारत बंद का नारा देती हैं, हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमारी समझ में यह बात आती है कि आखिर यह बंद का नारा क्यों दिया गया है ? आवाम को हुकूमत से शिकायत होती है, तब शहर बंद होते हैं । किसी मिल को आपने देखा होगा, अगर वहां की यूनियन ने बंद करवा दिया तो वहां भी हक की ही लड़ाई हमें देखने को मिलेगी ।

यूनियन वाले कहते हैं कि मिल का मालिक हरामखोर है । हमसे आठ घंटे की ड्यूटी लेता है और छह घंटे का पैसा देता है । इसलिए हमने स्ट्राइक कर रखी है । मिल-मालिक से हम पूछते हैं कि आखिर मजदूरों ने क्यों स्ट्राइक कर रखी है ; तो वह कहते हैं कि मजदूर कामचोर हो चुके हैं । ड्यूटी आठ घंटे की है । चार घंटा तो ड्यूटी करते हैं और चार घंटा गप्पबाजी में गुजार देते हैं । पता यह चला कि आज दुनिया में लोगों में जो एक-दूसरे से शिकायत है वह सिर्फ हक न मिलने की है ।

इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हकदारों को उनका हक दिया जाय । जम्हूरी हकूमत में तो जम्हूरियत के माथे पर यह कलंक का टीका है कि किसी सूबे में इलैक्शन न हो, किसी सूबे में आवाम का इलैक्शन न हो और हर वक्त सदर-राज बना दिया जाए, हर वक्त गवर्नर-राज बना दिया जाए, हर वक्त मार्शल ला का माहोल पैदा कर दिया जाए । आखिर में इस बिल को पास करवाते हुए इसे उम्मीद और ख्वाहिश के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि आइंदा काश्मीर में आवाम के हुकूक की जम्हूरी बहाली होगी और इस तरह वे लोग अपने मुकद्दर का फैसला हमारी मरकजी सरकार के तावुन से करते रहेंगे ।

खूब की सैरे-चमन, फूल चुने शाद रहे ।
बागबां जाता हूं, गुलशन तेरा आबाद रहे।

शुक्रिया ।

مولانا عبید اللہ خاں اعظمی (اتر پردیش):

شکریہ مسٹر وائس چیئرمین۔ سر جناب عالی کبھی کبھی انسان کی کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی بات کی تائید کرنی پڑتی ہے۔ اس حالت میں ہمیں مجبوراً کشمیر کے بجٹ کی تائید صرف اس لئے کرنی پڑ رہی ہے کہ جب جموں اینڈ کشمیر میں ریاستی اسمبلی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ قانوناً اس پارلیمنٹ کو کشمیر کا بجٹ پاس کرنا ہوگا۔ لیکن بار ہا ایسی حالت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس لئے جتنی جلدی ہو سکے کشمیر میں الیکشن کروا کر اس کام کو وہاں کی ریاستی اسمبلی کے حوالے کر دینا چاہیئے۔ قانون کے احترام اور کشمیری عوام کی ضرورتوں کے پیش نظر بجٹ تو ہمیں پاس کروانا ہی ہے مگر میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ہند کہتی ہے کہ کشمیر میں الیکشن کے لئے حالات سازگار نہیں ہیں لیکن میں حکومت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آسام گن پریشد کی منتخب حکومت کو چندر شیکھر سرکار برخاست کر رہی تھی۔ تو اس نے "الفا" آتنک وادیوں کو خاص وجہ قرار دیا تھا اور صاف لفظوں میں چندر شیکھر سرکار نے کہا تھا کہ آسام کے حالات کشمیر سے بھی زیادہ بدتر اور خراب ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں آسام میں اسمبلی کے الیکشن کروائے گئے اور آسام میں ریاستی حکومت قائم ہو گئی۔ اس لئے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جب حکومت کے کہنے کے مطابق کشمیر سے زیادہ حالات خراب آسام میں ہیں تو پھر کشمیر میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے لئے تو بہت تعجب کی بات ہے بار بار کشمیری عوام کو حق رائے دہندگی سے محروم رکھنا کیا ان کے جمہوری حقوق کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ الیکشن نہ کروانے کے کارن کشمیر میں جو آتنک وادی طاقتیں ہیں۔ میرے خیال سے ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور وہ کشمیر کے سادہ لوح عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ کشمیری عوام ہندوستان سے الگ ہٹ کر ایک اکائی ہیں جن کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس طرح وہ لوگ ملک کی وحدت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ کشمیری عوام بھولے بھالے ہونے کے ناطے انکی باتوں میں بھی آتے ہیں۔ آج کے مخصوص آتنک وادی حالات میں اگر ریاست جموں و کشمیر میں ان کی اپنی حکومت ہوتی اور مرکز میں بھی ان کے نمائندے ہوتے تو ان کو ہر طرح

سکا بھی بجٹ کے ذریعہ اظہار ہوتا ہے اور عوامی زندگی کی مادی ضروریات کی تکمیل بھی بجٹ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اسلئے بجٹ پر بحث و مباحثہ ہمارے یہاں بھی ہوتا رہتا ہے۔ جہاں عوام کے نمائندے اپنی علاقائی ضرورتیں اور مسائل کو ہاؤس میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پورے ملک اور ملک کے ہر علاقہ کے چھوٹے بڑے مسائل کی ایک تصویر پارلیمنٹ کے اندر ابھرتی ہے اور بجٹ اپنے لمبے بازوؤں میں تمام مسائل کو سمیٹ کر اس کے حل کی ایک تصویر پیش کر دیتا ہے۔ لیکن جس ریاست میں اسمبلی نہیں ہوتی ہے اس کا بجٹ نوکر شاہی تیار کرتی ہے۔ اور ہم جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو کشمیر کا بجٹ پاس کر رہے ہیں اس پر بھی اس علاقہ کے مسائل کو دیکھنے والی نہ کشمیری اسمبلی کے ممبروں کی نگاہ ہے اور نہ کشمیر سے چن کر آنے والے ممبران پارلیمنٹ کی نگاہ ہے۔ ایک مسلا ریہ صاحب کو چھوڑ کر لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں کوئی بھی کشمیر کا نمائندہ نہیں ہے جو وہاں کے مسائل کے پس منظر میں اس بجٹ پر اظہار خیال کر سکے۔ مالک میں اب تم جب پاس

سے قومی دھارا میں جوڑنے میں ہمیں آسانیاں ملتیں۔

جناب عالی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکا کی آزادی کی لڑائی کی شروعات جس نعرہ سے ہوئی تھی وہ نعرہ یہ تھا کہ "نمائندگی نہیں تو ٹیکس نہیں"، کیا آپ کشمیر کے الگاؤ واد کو بھی یہ نعرہ دینا چاہتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ میں ان نمائندگی نہیں اس حکومت کے لیے ان کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں یہ بات بہت ہی خطرناک ہے۔ وہاں کے عام عوام ہندوستانی ہیں ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اور تقسیم وطن کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا کہ کشمیری عوام نے ہندوستان کے ساتھ لڑنے میں اپنی ایک تاریخ بنائی تھی۔ اس لیے ملک کی سالمیت اور قومی ایکتا کے لیے نیز کشمیریوں کی بھلائی کے لیے جتنا جلد ممکن ہو الیکشن کروا دینا ہی بہتر ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر کا اگلا بجٹ ان کی اپنی اسمبلی میں پاس ہوگا اور تمام پارٹیاں قومی مفاد میں اس کا تعاون بھی کریں گی۔

جناب من۔ جمہوری ملک اور جمہوریت میں بجٹ کا مطلب جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ عوامی جذبات اور خواہشات

کمزوریوں کے تحت کشمیر کے مسائل اب تک ہم حل کرنے میں مایوس اور محروم دکھلائی دیتے ہیں۔ آج پاکستان کی سرزمین سے کشمیری عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں وہ ساری سازشیں بے نقاب ہو کر پوری دنیا کے پریس میں اور پوری دنیا کے ماحول میں آ چکی ہیں۔ جب ہماری ہی سرحد پر ایک ایسا ملک بیٹھا ہوا ہے جو کسی بھی شکل میں ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور کشمیر کو ہمارے لیے ایک متنازعہ فیہہ مسئلہ بنا کر آئے دن ہمیں اُلجھائے رکھتا ہے ایسی صورت میں ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ نہایت ہی نازک ترین سوچ کے ساتھ کشمیر کے مسائل کا مستقل کوئی حل نکالے۔ جس صوبہ میں بھی جناب عوام کی حکومت ہوتی ہے اس صوبہ میں عوام اپنے صوبہ کی بھلائی کے لیے اپنی اسمبلی میں اپنی سرکار سے لڑ جھگڑ کر اپنے صوبہ کے حسین خواب کو شرمندۂ تعبیر کرواتے ہیں۔ آج ہم جو بجٹ پاس کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بجٹ ہمارا یقین کی بنیاد پر نہیں قیاف اور قیاس کی بنیاد پر پاس ہونے جا رہا ہے۔ اگر اسمبلی ہوتی وہاں ایم۔ ایل۔ اینز کروالیں اور کروادیں۔ "ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے۔ مانو نہ مانو جانِ جہاں اختیار ہے"۔

جناب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو حالات ہیں ان حالات نے ہمارے پورے ملک کو متفکر کر رکھا ہے۔ کشمیر کیلئے بے پناہ دولت بھی ہم شروع سے ہی خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں۔

"مریضِ عشق پر لعنت خدا کی
مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی"

ہم نے جتنا زیادہ تعمیری انداز سے کشمیر کے لیے سوچا اتنا ہی زیادہ تخریبی کارروائیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ کشمیر میں ہم نے چاہا تھا کہ غربت کے ماحول سے کشمیری عوام کو نکالا جائے مگر آج بھی کشمیری عوام فاقہ کشی کا شکار ہے۔ کشمیر میں ہم نے چاہا تھا کہ تعلیم کو آگے بڑھایا جائے مگر آج بھی وہاں کے نوجوان تعلیم سے بے بہرہ دکھلائی دیتے ہیں۔ کشمیر کیلئے مرکزی حکومت بے پناہ روپیہ پیسہ خرچ کرتی ہے مگر یہ روپیہ پیسہ ان لوگوں کی غربت کو اب تک دور کر سکے نہ ان کے اندر تعلیم۔ تعمیر اور ترقی کا ہی کوئی جذبہ پیدا کیا جا سکا۔ ہمیں اپنی ان کمزوریوں کو کنگھالنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ان کمزوریوں پر نگاہ رکھنا ہوگا۔ جن

ایسا جنت بے نظیر کشمیر آج جہنم کی زمین پیش کر رہا ہے۔ وہ کشمیر جہاں سے محبت کے بادل اٹھتے تھے اور پیار کی شبنم برسا کرتی تھی۔ آج وہاں سے نفرت کے بادل اٹھتے ہیں اور خون کا پانی برس رہا ہے۔ وہ لہولہان کشمیر آج رو رہا ہے۔ اپنی قسمت پر۔ بھارت ماتا کے فرزندوں کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم وہاں کی اس کمی کو دور کر دیں۔ جس کمی کی وجہ سے شک و شبہات کے بادل اٹھتے رہتے ہیں۔ اور ہم اپنے ملک کی عزت و سلامتی کے لیے مستقلاً خطرہ پاتے ہیں۔

کشمیر کی خوبصورتی کے سلسلہ میں برادر گرامی جناب بیکل "اتساہی" ایم۔ پی۔ جو اس ہاؤس کے معزز ممبر ہیں انہوں نے اپنی نظم کا ایک بند پیش کیا ہے جسے میں ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بیکل صاحب کی شخصیت اور انکی شاعرانہ عظمت غیر ممالک میں بھی ہندوستانی عوام کی عظمت کا اظہار بنتی ہے جو اپنے اس دیش میں بہترین شاعر کی حیثیت سے ابھرے ہیں۔ اور قومی شاعر کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ہاؤس کے لوگوں کی توجہ چاہوں گا انہوں نے چُن کر آتے۔ پارلیمنٹ کا الیکشن وہاں ہوا ہوتا۔ وہاں سے عوامی نمائندے آتے تو آج وہ بتلاتے کہ کشمیر کے کس ضلع میں کشمیر کے کس خطّے میں۔ کشمیر کے کس حصّہ میں کشمیر کی کس برادری میں کشمیر کے کس خاندان میں کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا مصیبتیں موجود ہیں۔ مگر ان کی مصیبتوں کو کم کرنے کیلئے ہم اس طرح سے بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں جس طرح کوئی آدمی اٹکل اور قیاس اور وہم کے ساتھ ہوا اور فضا میں کوئی تیر چلا دے۔

کسی بھی جمہوری ملک میں یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ اس ملک کے عوام کو انکا جمہوری حق رائے دہندگی دے دیا جائے۔

جہاں جہاں بھی جس جس صوبہ میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں ان صوبوں سے نفرتوں کے بادل اٹھتے ہیں اور دہشتوں کا پانی برستا ہے انسانیت کی کھیتی میں کال پڑ جاتا ہے۔ وہ کشمیر جو پھولوں کی وادی کہلاتا ہے وہ کشمیر جس میں جو ہی اور بیلا اگتے ہیں وہ کشمیر جو اپنے دامن میں سوسن اور یاسمین رکھتا ہے وہ کشمیر جو گلشن بنا ہوا ہے وہ کشمیر جس کے لیے شاہ جہاں نے کہا تھا۔

"اگر جنت کہیں ہوتی زمیں پر
یہیں ہوتی یہیں ہوتی یہیں پر"

جائیں۔ الیکشن ہی وہاں کے مسائل کا حل ہوگا۔ وہاں کی نمائندہ سرکار آئے گی۔ وہ اپنا بجٹ پیش کرے گی۔ اپنے عوام کی ضرورتوں کا خیال رکھے گی۔ مرکزی حکومت اگر وہاں کی حکومت کے پیش کردہ بجٹ کے بعد بھی وہاں کے لوگوں کی سمسیاؤں اور پریشانیوں کو محسوس کرتی ہے تو مرکزی حکومت کو آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیں۔ میں امید کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ اس بجٹ کی تائید کر رہا ہوں اس بجٹ کی منظوری کی تائید کر رہا ہوں کہ اب آگے جو بجٹ آئے گا وہ ہماری پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا۔ بلکہ کشمیر کی ریاستی اسمبلی میں بجٹ آئے گا۔ تاکہ لوگوں کے حق محفوظ ہو جائیں۔ یاد رکھیے اگر حقدار کو اس کا حق نہیں ملا۔ تو خون کی لہریں کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے اگر حقدار کو اس کا حق نہیں ملا تو نفرت کے بادل کبھی نہیں ہٹ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بچانے کے لیے ایک بڑا اچھا آدرش دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ : ـــــ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔

"اے لوگوں اگر دنیا میں امن چاہتے ہو چین چاہتے ہو۔ سکون چاہتے ہو۔ کشمیر کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے۔ آپ اسے سامنے رکھیں۔

"جس سرزمین پہ لالہ و گل کی بہار تھی
جس خلد میں تھی حسن و محبت کی بارشیں
جھرنوں کی لے پہ گاتی ہوئی چلتی تھی ہوا
آج نفرت کی لے پہ گاتی ہوئی ہوا چل رہی ہے"

شاعر کے نازک خیال کو دیکھئے اور کشمیر کی وادی میں کھلنے والے ان گل بوٹوں کی نزاکت کو محسوس کیجئے جن سے ہمیں محبت کی خوشبو ملتی تھی۔ اور سارا جہاں اگر کشمیر کے پھولوں کی خوشبو میں اپنے موسم جان کو معطر کر کے جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ :

جھرنوں کی لے پہ گاتی ہوئی چلتی تھی ہوا
رنگ چنار میں تھی وہیں موسموں کی آگ
کیسر کی بو میں ہند کے اتہاس کا سرور
اس سرزمین پر آج ہے بارود کا غرور
الگاؤ داد خون خرابے کا دور ہے
انسانیت سلگتی ہے جہنم کا شور ہے۔
ڈل جھیل میں اب برف نہیں صرف خون ہے
ڈل جھیل میں اب برف نہیں صرف خون ہے
سرکار ہی بتائے یہ کیسا جنون ہے۔

اس جنون کو ختم کرنے کے لیے میں اپنی حکومت سے یہ ڈمانڈ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو کشمیر کی عوام کے حق رائے دہندگی کو بحال کیا جائے۔ وہاں الیکشن کروائے

شانتی چاہتے ہو تو ہر حقدار کا حق اسکو دیدو۔"

آج ساری دنیا میں لڑائی صرف حق کی ہو رہی ہے۔ کشمیر بند۔ آسام بند۔ بمبئی بند۔ کلکتہ بند۔ یہ جو بند کے نعرے لگتے ہیں۔ بعد میں پارٹیاں بھارت بند کا نعرہ دیتی ہیں۔ ہم جب اس کی تہہ میں جاتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آخر یہ بند کا نعرہ کیوں دیا گیا ہے۔ عوام کو حکومت سے شکایت ہوتی ہے تب شہر بند ہوتے ہیں۔ کسی مل کو آپ نے دیکھا ہوگا اگر وہاں کی یونین نے بند کروا دیا تو وہاں بھی حق کی ہی لڑائی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ یونین والے کہتے ہیں کہ مل کا مالک حرام خور ہے۔ ہم سے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی لیتا ہے اور چھ گھنٹے کا پیسہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اسٹرائیک کر رکھی ہے۔ مل مالک سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر مزدوروں نے کیوں اسٹرائیک کر رکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مزدور کام چور ہو چکے ہیں۔ ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی ہے۔ چار گھنٹے تو ڈیوٹی کرتے ہیں اور چار گھنٹے گپ بازی میں گذار دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آج دنیا میں لوگوں میں جو ایک دوسرے سے شکایت ہے وہ صرف حق نہ ملنے کی ہے اس لیے میں گذارش کروں گا کہ حقداروں کو ان کا حق دیا جائے۔ جمہوری حکومت میں تو جمہوریت کے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکہ ہے کہ کسی صوبہ میں الیکشن نہ ہو۔ کسی صوبہ میں عوام کا سلیکشن نہ ہو اور ہر وقت صدر راج بنا دیا جائے۔ ہر وقت گورنر راج بنا دیا جائے۔ ہر وقت مارشل لا کا ماحول پیدا کر دیا جائے۔ آخر میں۔ اس بل کو پاس کرواتے ہوئے اس امید اور خواہش کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ آئندہ کشمیر میں عوام کے حقوق کی جمہوری بحالی ہوگی اور اس طرح وہ لوگ اپنے مقدر کا فیصلہ ہماری مرکزی سرکار کے تعاون سے کرتے رہیں گے۔

"خوب کی سیر چمن۔ پھول چنے شاد رہے
باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔"

श्री रफीक आलम (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि कश्मीर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हमसे छीन नहीं सकती है। लेकिन, सबसे बड़ी मशायल हमारे सामने यह है कि जो हमारी बोर्डर स्टेट है चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो, असम हो, तमिलनाडू हो, वह डिस्टर्ब है। आखिर क्या वजह है? इसका पता करने के लिए हकुमत को गहराईयों में जाना पड़ेगा क्योंकि साजिस हो रही है कि किस तरह से हिन्दुस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए यही वजह है कि हमारी बोर्डर स्टेट डिस्टर्ब है। लेकिन, इसको हम ताकत के जरिए डिस्टेबलाईज नहीं कर सकते।

[illegible] महोदय, रूस की हालत आपने देखी है। उसकी बहुत ही ताकत है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, न्यूकलीयर पावर सब कुछ रहते हुए भी उसकी जो

[श्री रफीक आलम]

हालत है वह आपको और हम सभी को मालूम है। इतनी ताकत की बिना पर हम अगर जाएंगे तो शायद हिन्दुस्तान भी किसी न किसी दिन डिस्टेबलाईज हो जाएगा। इसलिए जरूरत अभी सोचने की है कि किस तरह से मुल्क मुतहिद रहे, किस तरह से मुल्क एक रहे, किस तरह से उन साजिशों का हम लोग मुकाबला करेंगे, जो हमारी ताकतें कर रही हैं? और, यह हम कर सकते हैं आवाम के जरिए, जनता के जरिए। वहां की जनता की जो मशायल है, चाहे पंजाब की हों, कश्मीर की हों, बंगाल की हों, असम की हों, तमिलनाडू की हों कहीं की हों, वहां की मशायल में हमको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा और लोगों के जरिए सोल्यूशन निकालना होगा। हम लोग अगर चाहेंगे कि साहब, यह गवर्नर को भेज दें वह वहां के लोगों पर गोली बरसाये और फिर ठंडा हो जाएगा। तो वह वक्त गुजर गया। अब लोग जान चुके हैं सब अपने हक के लिए। इसलिए जिस तरह चाहते हैं कि पंजाब में जल्द से जल्द इलैक्शन हों ताकि सिख भाइयों को यह कहने का मौका न मिले कि हिन्दुस्तान के हर हिस्से में चुनाव हो रहा है और हिन्दुस्तान के एक हिस्से पंजाब में चुनाव नहीं हो रहा, इसी तरह से कश्मीर भाई, जो हमारे साथ आए, उस वक्त आए जबकि हमें सख्त जरूरत थी, अब वहां भी चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। चुनाव होने के बाद वहां की आवाम फैसला करेगी। वहां हमारे साथ तो है ही और रहेंगे ही, लेकिन उनको यह कहने का मौका न मिले कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में तो सबकी अपनी-अपनी सरकार है, लेकिन हमारे यहां नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वी० पी० सिंह की सबसे जबरदस्त भूल जो हुई है वह यह है कि वहां एक असैम्बली थी, वहां असैम्बली के मैम्बर थे, उनके जरिए वहां के लोगों को अपने साथ रखना था। चूंकि अगर हम यह सोचेंगे कि साहब, जिस तरह से अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर वायसराय के जरिए राज किया, इस तरह से हम अगर रूल करेंगे तो मुश्किल है। इसलिए जरूरत इस बात की है जो भी स्टेट हो—असम हो, बंगाल हो पंजाब हो, तमिलनाडू हो, हर जगह हम आवाम के जरिए ही राज कर सकते हैं और मुल्क को एक रख सकते हैं। इसलिए वहां असेम्बली का चुनाव बहुत जरूरी है। खासकर के हमको बार्डर स्टेट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

आप जानते हैं कि कश्मीर में गरीबी बहुत है, मुझे कश्मीर में जाने का मौका मिला, गांव में वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। सदर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां प्लेन में तो गांव काफी बड़े हैं लेकिन वहां हिल्स में कुछ गांव यहां हैं, कुछ गांव दूसरी तरफ हैं और छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल के लिए पांच या छः मील दूरी पर जाना पड़ता है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि हर गांव में प्राइमरी स्कूल हो जाएं, मिडिल स्कूल हो जाएं, उसके बाद हाई स्कूल और कालेज वहां खोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम कश्मीर को दें और उनकी मोबिलिटी हो, क्योंकि जब तक वे लोग हमसे नहीं मिलेंगे और हम उनसे नहीं मिलेंगे तब तक न वे हमको जानेंगे और न हम उनको जानेंगे और यह थ्रू कम्यूनिकशन एण्ड एजूकेशन ही हो सकता है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि वहां लोकल पब्लिक को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में

मौका देना चाहिए । जब बंगाल का चीफ मिनिस्टर वहां का हो सकता है, तो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर वहां का क्यों नहीं हो सकता ? जब बंगाल के चीफ सेक्रेटरी बंगाल के ही हो सकते हैं तो कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं कश्मीर के ही हो सकते ? इसलिए हमको यह देखना पड़ेगा कि उनके भी जज्बात हैं उनके भी एहसासात् हैं और उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में मौका देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको आई० ए० एस० आई० पी० एस० करके हमको दूसरे स्टेट में भेजना चाहिए, जैसे कोई चला जाए मद्रास में, बंगाल में, बम्बई में, ताकि एक दूसरे से मिलने जुलने का रास्ता खुले । इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जो बजट लाए हैं, वह ठीक है और मौलाना आजमी साहब ने भी कहा कि आइंदा का बजट वहां की असेम्बली ही पास करेगी, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का माहोल दुरुस्त किया जाए और फिर आपस में मिलने जुलने का एक रास्ता अख्तियार किया जाए और वह हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहां हम एजूकेशन को कामन नहीं करते । इसलिए वहां की गरीबी और वहां की इलिटरेसी, इन दोनों को दूर करना बहुत जरूरी है । आप जानते हैं कि जब एक आदमी महल में सोता है और दूसरा आदमी झोंपड़ी में सोता है, तो झोंपड़ी में सोने वाला आदमी हिन्दुस्तानी होता है और महल में सोने रहने वाला इंगलिस्तानी होता है । लेकिन उसके दिल में महल के खिलाफ नफरत इसलिए हो जाती है क्योंकि वह सोचता है कि इसको सब कुछ हासिल है और हमें कुछ भी नहीं । यही कश्मीर का हाल है । वे सोचते हैं कि 44 साल तक हम लोग हिन्दुस्तान में रहे लेकिन हमारी गरीबी अब तक दूर नहीं हुई । उनको उस वक्त लालच हुआ होगा कि पाकिस्तान में हम लोग जायेंगे तो भूखे मरेंगे लेकिन हिन्दुस्तान में खुशहाल होंगे । क्योंकि इकनामिक कन्डीशन जो होती है, वह इंसान को मजबूर करती है सोचने पर । इसलिए जरूरत इस बात की है कि कश्मीर के भाइयों को हम लोग गले से लगायें, बजाए गोली के हम लोग उनको मुहब्बत से अपने साथ लगाएं और वहां जितनी जल्दी हो, हम वहां चुनाव करा दें, ताकि उनको यह कहने का मौका न मिले कि हिन्दुस्तान तो कहता है कि कश्मीर हिन्दुस्तान का अटूट हिस्सा है, पर कश्मीर को चुनाव से वंचित रखता है । हर जगह चुनाव होते हैं तो वहां क्यों नहीं होते ?

एक चीज हमें और भी ख्याल में रखनी होगी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें लोकल पीपुल्स को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए ताकि उनमें यह फीलिंग न हो कि हमारा एस०डी०ओ० और कलेक्टर तो सब बाहर से आते हैं । हमारे साथ यह रवैया क्यों अख्तियार करते हैं ? क्या कश्मीर हिन्दुस्तान का एक कालोनी है ? यह उनको सोचने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए और पाकिस्तान जो वह फीलिंग पैदा करता है, वह जान-बूझ कर करता है ताकि कश्मीर हिन्दुस्तान से अलग हो जाये, लेकिन हमें इस बात का अहसास होना चाहिए और हमें यह सोचना भी चाहिए कि हम कोई काम ऐसा न करें जिससे कि वहां के लोग हमसे बदजन हो जायें । हमें उनकी मुहब्बत चाहिए और हमें भी उनको मुहब्बत देनी चाहिए ।

और इस लिहाज से मैं कहूंगा कि धारा 370 यह क्यों हो रहा है ।

سے ان سازشوں کا ہم لوگ مقابلہ کریں گے جو باہری طاقتیں کر رہی ہیں اور وہ ہم کر سکتے ہیں عوام کے ذریعہ۔ جنتا کے ذریعہ۔ وہاں کی جنتا کے جو مسائل ہیں۔ چاہے پنجاب کی ہو۔ کشمیر کی ہو۔ بنگال کی ہو۔ آسام کی ہو۔ تمل ناڈو کی ہے۔ کہیں کی بھی ہو۔ وہاں کے مسائل میں ہم کو بہت گہرائی میں جانا پڑے گا اور لوگوں کے ذریعہ سولیوشن نکالنا ہوگا۔ ہم لوگ اگر چاہیں گے کہ صاحب یہ گورنر کو بھیج دیں۔ وہ وہاں کے لوگوں پر گولی برسائے اور پھر ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ وقت گزر گیا۔ اب لوگ جاگ چکے ہیں سب اپنے حق کے لئے۔ اس لئے جس طرح چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جلد سے جلد الیکشن ہوں تاکہ سکھ بھائیوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہندوستان کے ہر حصہ میں چناؤ ہو رہے ہیں اور ہندوستان کے ایک حصہ پنجاب میں چناؤ نہیں ہو رہا ہے اسی طرح سے کشمیری بھائی۔ جو ہمارے ساتھ آئے۔ اس وقت آئے جبکہ ہمیں سخت ضرورت تھی اب وہاں بھی چناؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ چناؤ ہونے کے بعد وہاں کی عوام فیصلہ کرے گی۔ وہ ہمارے ساتھ تو ہیں ہی اور رہیں گے ہی لیکن ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں

شری رفیق عالم (بہار): اپ سبھا ادھیکش مہودے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو ہم سے چھین نہیں سکتی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو ہماری بارڈر اسٹیٹ ہے۔ چاہے پنجاب ہو کشمیر ہو آسام ہو تمل ناڈو ہو وہ ڈسٹرب ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے اس کا پتہ کرنے کے لئے حکومت کو گہرائیوں میں جانا پڑے گا۔ کیوں کہ سازش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہندوستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بارڈر اسٹیٹ ڈسٹرب ہیں۔ لیکن اس کو ہم طاقت کے ذریعہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے۔

مہودے۔ روس کی حالت آپ نے دیکھی ہے اس کی بہت بڑی طاقت ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ نیوکلیئر پاور سب کچھ رہتے ہوئے بھی اس کی جو حالت ہے وہ آپ کو اور ہم سبھی کو معلوم ہے۔ اتنی طاقت کی بنا پر اگر ہم جائیں گے تو شاید ہندوستان بھی کبھی نہ کسی دن ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ اس لئے ضرورت ابھی سوچنے کی ہے کہ کس طرح سے ملک متحد رہے۔ کس طرح سے ملک ایک رہے۔ کس طرح

میں تو سب کی اپنی اپنی سرکار ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے۔

آپ سبھا ادھیکش مہودے۔ وی۔ پی۔ سنگھ کی سب سے زبردست بھول جو ہوئی ہے وہ یہ کہ وہاں ایک اسمبلی تھی۔ وہاں اسمبلی کے ممبر تھے۔ ان کے ذریعہ وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ چوں کہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ صاحب جس طرح سے انگریزوں نے ہندوستان پر وائسرائے کے ذریعہ راج کیا۔ اس طرح سے ہم اگر رول کریں گے تو مشکل ہے۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی اسٹیٹس ہوں۔ آسام ہو، بنگال ہو، پنجاب ہو، تمل ناڈو ہو۔ ہر جگہ ہم عوام کے ذریعے ہی راج کر سکتے ہیں اور ملک کو ایک رکھ سکتے ہیں۔ اس لئے وہاں اسمبلی کا چناؤ بہت ضروری ہے۔ خاص کر کہ ہم کو بارڈر اسٹیٹ کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیئے

آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں غریبی بہت ہے۔ مجھے کشمیر میں جانے کا موقع ملا۔ گاؤں میں وہاں غریبی بہت زیادہ ہے صدر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پلین میں تو گاؤں کافی بڑے ہیں لیکن وہاں ہلس میں کچھ گاؤں یہاں ہیں۔ کچھ دوسری جگہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کیلئے پانچ پانچ میل دوری پر جانا پڑتا ہے۔ اس لئے کوشش یہ ہونی چاہئیے کہ ہر گاؤں میں پرائمری اسکول ہو جائے۔ مڈل اسکول ہو جائے اس کے بعد ہائی اسکول اور کالج وہاں کھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوویدھا ہم کشمیر کو دیں اور ان کی موبیلٹی ہو کیوں کہ جب تک وہ لوگ ہم سے نہیں ملیں گے اور ہم ان سے نہیں ملیں گے تب تک نہ وہ ہم کو جانیں گے اور نہ ہم ان کو جانیں گے اور یہ تھرو کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن ہی ہو سکتا ہے۔

تیسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ وہاں لوکل بیلٹ کو ایڈمنسٹریشن میں موقع دینا چاہیئے۔ جب بنگال کا چیف منسٹر وہاں کا ہو سکتا ہے تو کشمیر کا چیف منسٹر وہاں کا کیوں نہیں ہو سکتا۔ جب بنگال کے چیف سیکریٹری بنگال کے ہی ہو سکتے ہیں تو کشمیر کے چیف سیکریٹری کشمیر کے ہی کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بھی جذبات ہیں۔ ان کے بھی احساسات ہیں۔ اور ان کو لوکل ایڈمنسٹریشن میں موقع دینا چاہیئے اور زیادہ سے زیادہ ان کو آئی۔ اے۔ ایس اور آئی۔ پی۔ ایس کر کے ہم کو دوسرے اسٹیٹ میں بھیجنا چاہیئے جیسے کوئی چلا جائے مدراس میں۔ بنگال میں۔ بمبئی میں تاکہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا راستہ کھلے۔

اس بات کی ہے کہ کشمیر کے بھائیوں کو ہم لوگ گلے سے لگائیں، بجائے گولی کے ہم لوگ محبت سے ان کو اپنے ساتھ لگائیں اور وہاں جتنی جلدی ہو ہم وہاں چناؤ کرا دیں تاکہ ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہندوستان تو کہتا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے پر کشمیر کو چناؤ سے وانچت رکھتا ہے۔ ہر جگہ چناؤ ہوتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں ہوتے

ایک چیز ہمیں اور بھی خیال میں رکھنی ہوگی کہ لوکل ایڈمنسٹریشن میں ہمیں لوکل پیپل کو زیادہ سے زیادہ لینا چاہیئے تاکہ ان میں یہ فیلنگ نہ ہو کہ ہمارا ایس۔ ڈی۔ او۔ اور کلکٹر تو سب باہر سے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ کیا کشمیر ہندوستان کی ایک کالونی ہے۔ یہ ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیئے اور پاکستان جو وہاں فیلنگ پیدا کرتا ہے وہ جان بوجھ کر کرتا ہے تاکہ کشمیر ہندوستان سے الگ ہو جائے۔ لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیئے اور ہمیں یہ سوچنا بھی چاہیئے کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں۔ ہمیں ان کی محبت چاہیئے اور ہمیں بھی ان کو محبت دینی چاہیئے اور اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ دھارا ۳۷۰ یہ کیوں ہو رہا ہے

To every action there is an equal reaction in the opposite direction.

اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ جو بجٹ لائے ہیں وہ ٹھیک ہے اور مولانا اعظمی صاحب نے بھی کہا کہ آئندہ کا بجٹ وہاں کی اسمبلی ہی پاس کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا ماحول درست کیا جائے اور پھر آپس میں ملنے جلنے کا ایک راستہ اختیار کیا جائے اور وہ ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک وہاں ہم ایجوکیشن کو کامن نہیں کرتے۔ اس لئے وہاں کی غریبی اور وہاں کی الٹریسی ان دونوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی محل میں سوتا ہے اور دوسرا آدمی جھونپڑی میں سوتا ہے تو جھونپڑی میں سونے والا ہندوستانی ہوتا ہے اور محل میں سونے رہنے والا انگلستانی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دل میں محل کے خلاف نفرت اس لئے ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کو سب کچھ حاصل ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں۔

یہی کشمیر کا حال ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ۴۴ سال تک ہم لوگ ہندوستان میں رہے لیکن ہماری غریبی اب تک دور نہیں ہوئی۔ اس کو اس وقت لالچ ہوا ہوگا کہ پاکستان میں ہم لوگ جائیں گے تو بھوکے مریں گے۔ لیکن ہندوستان میں خوشحال ہوں گے۔ کیوں کہ اکنامک کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے سوچنے پر۔ اس لئے ضرورت

ہاؤس کا ڈویلپمنٹ نہیں ہوا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پیسہ ہم دیں وہ عوام کے لئے خرچ کیا جائے کچھ لوگوں کے لئے نہیں۔ تاکہ عوام کی ہمدردی ہمارے ساتھ رہے۔

ان الفاظ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پنجاب اور کشمیر میں جتنی جلدی ہو چناؤ کرایا جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاکستان کے پروپیگنڈہ کو ہم لوگ ختم کریں۔

[उपसभापति (श्री शकर दयाल) : पीठासीन हुए]

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : वाईस चैयरमैन सर, कश्मीर के बजट के बारे में अभी दो मौजूदा मैम्बरान ने जिन हालात का इजहार किया, मेरे ख्यालात भी कमोबेश नहीं है। इस में तो कोई चारा नहीं है सिवाए इसके कि इस बजट को पास कर दिया जाए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हुकूमतें हिन्द जो जिस संजीदगी के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए वह संजीदगी कहीं दूर-दूर तक नजर नहीं आती। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के हालात इधर तीन वर्षों के अंदर बहुत तेजी से बिगड़े हैं। जब तक फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी तब तक हालात एक हिसाब पर चल रहे थे। लेकिन मेरी पार्टी जिस बात के ऊपर एतराज करती है किसी भी रियासत में अगर कोई गैर कांग्रेसी हुकूमत आवाम के वोटों से बन जाए तो भी उस हुकूमत को बर्दास्त नहीं किया जाता है और उसको उलटने की कोशिशें होती है। इसकी मिसाल बहुत हैं और मेरे ख्याल में शायद ही कोई सूबा, रियासत ऐसा बचा हो जहां चुनी हुई हुकूमत तोड करके सदर राज न स्थापित किया गया हो। मौलाना ने एक बात बहुत पते की कही है कि जब किसी से उसका हक छीन लिया जाता है तो उसके दिल पर उसका

हर عمل کا ردعمل ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے صحیح یا غلط۔ اتنا غلط نعرہ دے دیا کہ آرٹیکل ۳۷۰ ختم کیا جائے۔ کشمیر کے لوگوں نے سوچا کہ آرٹیکل ۳۷۰ تو ہم کو اس وقت کے لوگوں نے دیا ہے یہ سنویدھان میں ہے۔ اس کو ختم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہندوستانی لوگ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی پوری زمین ہم لوگ خرید لیں اور ان لوگوں کو رفیوجی بنا دیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کی نیت ایسی نہیں ہے لیکن پروپیگنڈہ کرنے والے ان کو ہم سے خلاف کر رہے ہیں اور اس لئے پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے خلاف ایک نفرت جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہے۔ اس لئے ہمیں اس نفرت کی دیوار کو توڑنا ہے اور ہمیں ان لوگوں کو وہی حصہ دینا ہے جو ہندوستان کے دوسرے حصوں میں دیا جاتا ہے اور وہ ہے کہ اس کی غریبی کو ہم کیسے دور کریں اور اس میں الاٹمنٹ بھی ہوا ہے۔ میں فائنینس منسٹر کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں کی ایجوکیشن وہاں کا ٹورزم وہاں کے ایگریکلچر پر زیادہ سے زیادہ پیسہ دیا ہے لیکن صرف پیسہ دینے سے نہیں ہوگا وہاں ہمیں ماحول پیدا کرنا ہے کہ پیسہ جائز طور پر خرچ ہو۔ کشمیر میں کیا ہوا ہے کہ ہم سے روپے لیتے وہاں کے ڈیولپمنٹ کیلئے۔ کچھ لوگوں کا ڈیولپمنٹ ہوا لیکن کامن

शदीद रद्दे अमल होना बिल्कुल कुदरती बात है और इसकी वजह से पेचीदगी पैदा होती हैं, बेजारी पैदा होती है, नफरत का माहौल बनता है और हमारा मुल्क बजाए मुत्तहिद होने के और ज्यादा इंतजार की तरफ बढ़े जाता है। चुनांचे सबको यह बात याद है कि फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट दतोड़े जाने के बाद की ही हालात काबू से बाहर हो गए। अब अच्छा माहौल बनाने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन माहौल बनेगा कैसे ? हुकूमत जबान से चाहे कुछ भी कहे, मगर देखा यह जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वह बंदूक की नली पर भरोसा कर रही है, सिक्योरिटी फोर्स, आपकी मुसल्लाह फोज और पुलिस इनके ऊपर भरोसा किया जा रहा है और गवर्नर साहब लम्बे-चौडे बयानात देते हैं।

गवर्नर साहब हैं, वह लबें-चौडे बयानात देते हैं लेकिन अखबारों में जो रिपोर्ट छपती है उनसे यह पता चलता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जद में उनके जुल्म का शिकार ज्यादातर मासूम और बेगुनाह लोग हो रहे हैं और इससे और ज्यादा बदजनी बढ़ रही है। कश्मीर के लोग हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। यह सिलसिला कब तक चलेगा ? छः महीने पर सदर राज में तो सीक की जाती है, बजट पास किया जाता है और हुकूमत यह कहती है कि हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कश्मीर में एक चुनी हुई हुकूमत आएगी मगर उसकी नौबत नहीं आती। इस वक्त जैसे हालात हैं, उनसे तो यह महसूस होता है कि कश्मीर में कोई हुकूमत नहीं है, कोई कानून नहीं है। किसी भी आदमी को चाहते हैं, उठाकर ले जाते हैं, अपनी कैद में रखते हैं और उसके बाद सोदेबाजी होती है कि इतने लोगों को रिहा किया जाए तो हम उसको छोड़ेंगे और ये मामलात भी इंतहाई खतरनाक सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं।

अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं, खास करके गैर-सरकारी, उनके दिल में जबर्दस्त अंदेश पैदा हो गए हैं। वे अपने आपको गैर-सलामत महसूस करते है और कोई सियासी पार्टी वहां काम नहीं कर पा रही है। मेरी पार्टी सी०पी०आई० एम० के लोग भी कश्मीर से चले आने पर मजबूर हुए हैं, जम्मू में आबाद हैं। दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। खुद नेशनल कांफ्रेस जो वहां की पार्टी है, अब उसके अंदर भी इंतशार पैदा हो गया है। फारूख अब्दुल्ला का कहीं पता नहीं है और मरकजी हुकूमत और कश्मीर के अवाम के बीच में दरम्यानी कड़ी क्या है यह कहीं नजर नहीं आता। तो इस प्रकार की क्या कोशिश हूकूमत कर रही है कि कश्मीर के आवाम को एतमाद में लेने के लिए, उनके दिल में भरोसा पैदा करने के लिए कुछ किया जाए। कोई बात ऐसी देखने में नहीं आ रही है। मेरी सलाह यह है कि इस तरह वक्त गुजरता चला जाएगा और मसला-ए-कश्मीर एक जरबुलमिस्ल बन चुका है। कोई संगीन मसला आता है तो लोग कहते हैं कि भइया यह मसला तो मसला-ए-कश्मीर से भी ज्यादा टेढ़ा है। ऐसा एक जरबुलमिस्स बन चुका है और इसके लिए वही ताकतें जिम्मेदार हैं जो इस मुल्क को सही रास्ते पर ले जाने से हमेशा कतराती हैं।

मैं समझता हूं कि दफा 370 को बरकरार रखना चाहिए। उसको हटा देने से काश्मीर के मसले को हल करने में मदद नहीं मिलेगी और मेरी सलाह यह है कि हुकूमत इस बजट को पास करने के बाद फौरन तमाम सियासी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाए और ये दरियाफ्त करे कि किसके जरिए दरम्यानी कड़ी हासिल करने की कोशिश कामयाब हो सकती है। इसके जरिए ही एक रास्ता निकल सकता है। आज कश्मीर की अवाम यह समझती है कि उनकी इज्जत-आबरू, उनका मजहब उनकी जमीन, उनका कल्चर महफूज नहीं है लेकिन यह घबराहट उनके अंदर से दूर हो सकती है और वे इस कौमी धारा में शामिल होने के लिए अपने आपको तैयार कर सकते हैं। इसलिए तमाम उन लोगों के ताबून की जरूरत है जो मुल्क को मुत्तहिद रखना चाहते हैं, सैक्यूलरिज्म को बचाना चाहते हैं और इस मुल्क को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही मुझे कहना है।

کہ جب کسی سے اس کا حق چھین لیا جاتا ہے تو اس کے دل پر اس کا شدید ردعمل ہونا بالکل قدرتی بات ہے اور اس کی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ نفرت کا ماحول بنتا ہے اور ہمارا ملک بجائے متحد ہونے کے اور زیادہ انتشار کی طرف بڑھ جاتا ہے چنانچہ سب کو یہ بات یاد ہے کہ فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ توڑے جانے کے بعد ہی۔ حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اب اچھا ماحول بنانے کی کوشش ضرور کی جانی چاہیئے۔ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن ماحول بنے گا کیسے۔ حکومت زبان سے چاہے کچھ بھی کہے۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندوق کی نالی پر بھروسہ کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورس۔ آپ کی مسلح افواج اور پولیس۔ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے اور گورنر صاحب لمبے چوڑے بیانات دیتے ہیں لیکن اخباروں میں جو رپورٹ چھپتی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیکیورٹی فورسیز کی زد میں ان کے ظلم کا شکار زیادہ تر معصوم اور بے گناہ لوگ ہو رہے ہیں اور اس سے اور زیادہ بدظنی بڑھ رہی ہے۔ کشمیر کے لوگ ہم سے

شری محمد امین "مغربی بنگال": وائس چیئرمین سر، کشمیر کے بجٹ کے بارے میں ابھی دو موجودہ ممبران نے جس حالات کا اظہار کیا۔ میرے خیالات بھی کم و بیش وہی ہیں۔ اس میں تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس بجٹ کو پاس کر دیا جائے لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور حکومت ہند کو جس سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے وہ سنجیدگی کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر کے حالات ادھر تین ورشوں کے اندر بہت تیزی سے بگڑے ہیں۔ جب تک فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ تھی تب تک حالات ایک حساب پر چل رہے تھے لیکن میری پارٹی جس بات کے اوپر اعتراض کرتی ہے کہ کسی بھی ریاست میں اگر کوئی غیر کانگریسی حکومت عوام کے ووٹوں سے بن جائے تو بھی اس حکومت کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے اور اس کو الٹنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ہیں اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی صوبہ ریاست ایسا بچا ہو۔ جہاں چنی ہوئی حکومت کو توڑ کر کے صدر راج نافذ نہ کیا گیا ہو۔ مولانا نے ایک بات بہت سچے کی بات کہی ہے

دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ ہر چھ مہینے میں صدر راج میں توسیع کی جاتی ہے۔ بجٹ پاس کیا جاتا ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد کشمیر میں ایک چنی ہوئی حکومت آئے گی۔ مگر اس کی نوبت نہیں آتی۔ اس وقت جیسے حالات ہیں۔ ان سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کشمیر میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کو چاہتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اپنی قید میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد سودے بازی ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کو رہا کیا جائے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے اور یہ معاملات بھی انتہائی خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔

اب جو سرکاری ملازمین ہیں۔ خاص کر کے غیر سرکاری۔ ان کے دل میں زبردست اندیشہ پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اور کوئی سیاسی پارٹی وہاں کام نہیں کر پا رہی ہے میری پارٹی سی۔ پی۔ آئی۔ ایم کے لوگ بھی کشمیر سے چلے آنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جموں میں آباد ہیں۔ دوسری پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے۔ نیشنل کانفرنس جو وہاں کی پارٹی ہے۔ اب اس کے اندر بھی انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ فاروق عبداللہ کا کہیں پتہ نہیں ہے اور مرکزی حکومت اور کشمیر کے عوام کے بیچ میں درمیانی کڑی کیا ہے۔ یہ کہیں نظر نہیں آتا۔

تو اس پرکار کی کیا کوشش حکومت کر رہی ہے کہ کشمیر کے عوام کو اعتماد میں لینے کے لئے ان کے دل میں بھروسہ پیدا کرنے کے لئے کچھ کیا جائے۔ کوئی بات ایسی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ میری صلاح یہ ہے کہ اس طرح وقت گزرتا چلا جائے گا اور مسئلہ کشمیر ایک ضرب المثل بن چکا ہے کوئی سنگین مسئلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئیا یہ مسئلہ تو مسئلہ کشمیر سے بھی زیادہ ٹیڑھا ہے۔ ایسا ایک ضرب المثل بن چکا ہے اور اس کے لئے وہی طاقتیں ذمہ دار ہیں جو اس ملک کو صحیح راستہ پر سے جانے سے ہمیشہ کتراتی ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ دفعہ ۳۷۰ کو برقرار رکھنا چاہئے۔ اس کو ہٹا دینے سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی اور میری صلاح یہ ہے کہ حکومت اس بجٹ کو پاس کرنے کے بعد فوراً تمام سیاسی پارٹیوں کی ایک میٹنگ بلائے اور یہ دریافت کرے کہ کس کے ذریعہ درمیانی کڑی حاصل کرنے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے

ذریعے ہی ایک راستہ نکل سکتا ہے۔ آج کشمیر کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کی عزت آبرو۔ ان کا مذہب۔ ان کی زمین ان کا کلچر محفوظ نہیں ہے لیکن یہ گھبراہٹ ان کے اندر سے دور ہو سکتی ہے اور وہ اس قومی دھارا میں شامل ہونے کے لئے ہم آپ کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس لئے ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے جو ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ سیکولرازم کو بچانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اتنا ہی مجھے کہنا ہے۔

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, इनकी पार्टी का टाइम पूरा हो गया।

श्री सुरेश जे. शाह (महाराष्ट्र) : वक्त किसका पूरा हो गया सरकार का या इनकी पार्टी का ?

श्री रजनी रंजन साहू : इन लोगों के बोलने टाइम खत्म हो गया।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : जब तक अमीन साहब और ओबैदुल्ला साहब बोल रहे थे तब तक आप सुन रहे थे और जब सुषमा जी खड़ी हुई तो तो माप व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री रजनी रंजन साहू : जब थुमार साहब खड़े होते हैं हम तब व्यवधान डालते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय इस समय सदन में जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति शासन के तहत शासित होने के कारण यह आवश्यक है कि भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के बजट को पास करे। लेकिन इस संवेधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मैं सबसे पहले एक प्रश्न वित्त राज्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि सरकार और कितने वर्ष तक हमसे जम्मू-काश्मीर का बजट पास कर वायेगी ? अभी भाई आजमी ने इस चर्चा में यह उम्मीद जाहिर की कि अगले साल यह बजट यहां पास न हो कर वह। की रियासते ऐसेम्बली में पास होगा लेकिन मैं उम्मीद नहीं आशंका जाहिर करती हूं और मेरी आशंका की बुनियाद है पंजाब। आप जानते हैं कि पिछले चार वर्षों से भारत की संसद लगातार पंजाब के बजट को पास कर रही है। संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा को भी पंजाब के संदर्भ में हमने पार कर लिया है। महोदय, आप तो स्वयं संविधान के ज्ञाता हैं, पंजाब के संदर्भ में जब भी मसला सदन में आता है, आप अपनी ओर से क्षोभ और पीड़ा रखते हैं। मैं धारा 356 की पंक्तियां पढ़कर बताना चाहती हूं कि कितना मेंडेटरी वह प्राविजन है, वह धारा जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसने ही एक पाबंदी संसद के ऊपर डाली थी कि —

No such Proclamation shall, in any case, remain in force for more than three years.

"in no case"

यानी किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति शासन की अवधि किसी प्रदेश में तीन साल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन 68वां संविधान संशोधन पारित करके इस अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है पंजाब के संदर्भ में इसलिए संदेह की निगाह जम्मू-कश्मीर के ऊपर मेरी पड़ती है क्योंकि 11 मई 198' को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और आज ही उसको 11 मई 1992 तक बढ़ा दिया और 5 वर्ष की अवधि पूरी कर दी। लेकिन जम्मू-काश्मीर में 18 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

शासन लागू हुआ था और तब से लेकर आज तक दो बार हम राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर चुके हैं। एक बार जम्मू-काश्मीर का लेखानुदान यानि वोट आन ऐकाउंट पास कर चुके हैं और आज हम यह बजट पास कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि सामान्यतः साधारण परिस्थिति में जो चीज वहां की विधान सभा के द्वारा पारित की जानी चाहिए थी उसे असाधारण परिस्थिति में भारतीय संसद् पारित कर रही है तो क्या वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि यह असाधारण परिस्थिति जम्मू-काश्मीर में कब तक रहने वाली है क्योंकि पंजाब के बारे में हमने देखा है कि 4 साल में हर 6 महीने बाद वैसा ही विधेयक लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा वैसी ही चेतावनी दी जाती है और सरकार के द्वारा फिर वैसा ही आश्वासन दिया जाता है और फिर थोड़ी नोकझोंक के बाद उसी तरह का विधेयक पारित हो जाता है। हर बार हमारी निगाह कुछ नई जानकारी प्राप्त करने के लिए उठती है, लेकिन मिलती है वही बासी जानकारी, वही उबाऊ जवाब।

महोदय, मुझे लगता है कि यथास्थिति में जीना हम लोगों की आदत हो गई है। यथास्थिति के शिकार लोग इसको अपनी नियति मान बैठे हैं। भारतीय संसद् और राज्य-सभा के पटल पर खड़ी हुई, सरकार के गृह मंत्री जी बैठे हैं, सरकार के वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि इस असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए भारत की संसद ने तमाम वह शक्तियां आपको दी हैं जो आपने मांगी। तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रप शासन लागू करना चाहा आपने जम्मू एंड काश्मीर आर्म्स फोर्सेज ऐक्ट पास करके स्थिति से निपटने के लिए विशेष शक्तियां अपने हाथ में लेनी चाहीं, सदन ने वह शक्ति आपको बक्शी। लेकिन तमाम चीजें होने के बावजूद जम्मू-काश्मीर में चुनौती क्या है? मैं आगे बढ़कर कहूं कि चुनौती दिनों-दिन क्यों बिगड़ रही है? शायद वहां यथास्थितिवाद बनाए रखने में कुछ निहित स्वार्थों का निहत स्वार्थ है। उनके हाथ में सरकार कठपुतली बनी हुई है। मैं कहना चाहती हूं कि आपके जो बजट प्रस्ताव हैं ये भी उस यथास्थितिवाद को दर्शाते हैं।

मैंने इस बजट के बारे में दस्तावेजों को पढ़ा है, जो वक्तव्य दिया है उसके साथ जो तीन कागजात दिए गए हैं उन तीनों दस्तावेजों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि बजट के किसी दस्तावेज को पढ़कर यह नहीं लगता कि यह बजट किसी संकटग्रस्त राज्य का बजट है। यह देखकर नहीं लगता कि इस बजट के अंदर किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने की क्षमता है। मैंने पूरे दस्तावेजों के सारे मदों को, सारे प्रावधानों को पढ़ा लेकिन इस बजट में न तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और न ही विस्थापितों के लिए किसी राहत कार्यक्रम की घोषणा की गई है। लगता है कि सामान्य परिस्थिति में बनाया हुआ एक सामान्य प्रदेश का बजट है जो केवल प्रशासन की संवेदन, हीनता की उजागर करता है। मैं पूछना चाहती हूं वित्त राज्य मंत्री महोदय से कि क्या दूरदर्शन के उस अपहरण के सिलसिले में जुड़ते हुए, कील, वाखल और खन्ना के केस, वहां के आतंकवादी संगठनों के द्वारा केवल अपहरण का न किया जाना बल्कि जब चाहे जिस को उठाकर ले जाना और महीनों-महीनों तक बंधक बनाए रखना, उनके हाथ-पांव काट देने की धमकियां तक दे डालना और अपने एक खूंखार से खूंखार साथी की रिहाई के बदले ही छोड़ने की घोषणा करना, क्या ये तमाम चीजें प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता महसूस नहीं कराता? अगर कराता है तो इस बजट में आपने कहा प्रावधान किया है? कहां से आप पैसा जुटायेंगे जिनके माध्यम से आप इन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था कर सकेंगे? मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वहां से निकले हुए विस्थापित एक लाख हिन्दू परिवार जो आज कैम्पों में, टैन्टों में, छावनियों में शरणार्थियों का जीवनयापन कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए जो आज घर से बेघर हुए दर-दर भटक रहे हैं उनके लिए कोई राहत कार्यक्रम की आवश्यकता शासन,

प्रशासन महसूस नहीं करता? अगर करता है तो कहां है आज के बजट में वह मद जिसके नीचे आपने इन राहत कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किया है? मैंने केवल ये दो मदें देखने के लिए पूरे दस्तावेज छान मारे लेकिन मुझे कहीं वह मद दिखाई नहीं पड़ी। पंजाब के बजट में तो है—रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन—राहत और पुनर्वास मद के नीचे वहां इन चीजों का प्रावधान किया गया है लेकिन काश्मीर के बजट में ऐसा कोई प्रावधान मुझे दिखाई नहीं दिया। हां, पिछले साल इन मदों में किया गया खर्च जरूर दिखाई दिया। मेरे पास वह वक्तव्य है जो 26 अगस्त, 1991 को वित्त राज्य मंत्री ने लोक सभा में दिया था। उसमें उन्होंने संशोधित अनुमानों के नीचे कहा है कि :

> "राजस्व व्यय में 30 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का कारण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों की सहायता, राहत कार्यों, सुरक्षा से संबंधित समस्याओं, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में राजस्व का व्यय किया जाना।"

यह पिछले वक्तव्य में कहा। आप जानते हैं जब पिछला बजट पास हुआ था उस समय स्थिति इतनी गम्भीर हो जाएगी वहां की असेम्बली को मालूम नहीं था इसलिए संशोधित अनुमानों के माध्यम से सरकार उस पैसे को ले, यह बात समझ में आती है। लेकिन आज स्थिति आपके सामने मुंह बाये खड़ी है। आपको उससे निपटना है लेकिन उससे निपटने के लिए इन बजट प्रावधानों में एक पैसे की व्यवस्था, पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। कैसे आप इससे निपटना चाहेंगे, यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं। क्या आप यह नहीं चाहते कि सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कोई पैसा खर्च किया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि इन विस्थापितों के राहत कार्यक्रम के लिए कोई पैसा खर्च किया जाए? वे विस्थापित अपने कारण नहीं हुए। उनका अपना कसूर नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि किन लोगों ने उनको आज घर से बेघर करके दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया? क्या कसूर है उन लाखों कश्मीरियों का जो अपना धंधा और सम्पदा छोड़कर दिल्ली और जम्मू की छावनियों में भटक रहे हैं? केवल यह कसूर है उनका कि वे कश्मीर की सर-जमीन पर बैठकर भारत माता की जय कहना चाहते हैं, केवल यह कसूर है उनका कि वे अपने यहां के स्कूल में अपने बच्चों को जन-गण राष्ट्रीय गान बुलवाते हैं। यह कसूर है उनका कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्यौहारों के दिन जब बाकी देश में इमारतों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाता है वे अपने कश्मीर की सर-जमीन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। इस कसूर की सजा उनको यही मिल रही है कि घर से बेघर कर दिया और सब कुछ छोड कर दिल्ली और जम्मू में भटक रहे हैं। किन लोगों के हाथ यह करवाया जा रहा है? वे लोग जो कश्मीर की सर-जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? उन लोगों के द्वारा यह करवाया जा रहा है जो सर-जमीन के चौराहे पर खड़े होकर राष्ट्रीय तिरंगे की होली जलाते हैं। उन सब के द्वारा यह करवाया जा रहा है जो अपनी घड़ी का समय पाकिस्तान की घड़ी के समय के साथ मिलाकर रखना चाहते हैं। उनके द्वारा यह करवाया जा रहा है जो रुपए की खरीद के बदले में पाकिस्तानी करेंसी आपको लौटाते हैं। सरकार सारी शक्तियों को अपने हाथ में समेटे हुए एक असहाय बनकर देखती है, निरीह बनकर खड़ी होकर देखती है। इसलिए मैं आप से कहना चाहती हूं कि क्या इस बजट में इस तहर का प्रावधान नहीं होना चाहिए? इस बजट में इस तरह के प्रावधानों का न होना सरकार की केवल संवेदनहीनता को नहीं दर्शाता बल्कि सरकार के मसले की गंभीरता को भी दर्शाता है।

जिस गम्भीरता से इस मसले को लिया जाना चाहिए उसकी दिलचस्पी में कमी को भी दर्शाता है, यह इस बजट पर मेरा पहला एतराज है। मेरा दूसरा एतराज यह है कि बजट तो हम पास करते हैं जम्मू-काश्मीर की एसेम्बली के लिए, जम्मू-काश्मीर राज्य के लिए और जम्मू-काश्मीर की विधान सभा की तरफ से, लेकिन मेरा आरोप है कि इस बजट में पैसे का दसवां हिस्सा भी जम्मू-लद्दाख

पर खर्च नहीं किया जाता है । आप जानते हैं कि तीन रीजन्स को मिला कर के काश्मीर बनता है । इस सदन के जरिये मेरा आरोप है कि बजट का 10 फीसदी हिस्सा जम्मू और लद्दाख पर खर्च किया जाता है और 90 फीसदी हिस्सा काश्मीर वेली पर खर्च किया जाता है । मैं यह आरोप कहने के लिए नहीं कह रही हूं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, जो बजट अनुदानों की मांगें हैं उनके माध्यम से मैं सन्दन के अदर पेश करना चाहती हूं । यह बजट अनुदानों की मांगों का जो विवरण है, चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं उनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूंगी । आपसे चाहूंगी कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपको मुझे पांच मिनट का फालतू समय भी देना पड़े तो मुझे दीजिएगा ।

मैं सबसे पहले मांग संख्या 6 को लेती हूं जो बिजली विकास विभाग से संबंधित है । इस वर्ष इसमें 41262 लाख 83 हजार रुपयों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके तहत जो बिजली विकास योजनायें काश्मीर में चल रही हैं, वित्त राज्य मंत्री जी, आपका ध्यान मैं उस तरफ दिलाना चाहती हूं । इस समय सरकार की ओर से चलने वाली सारी बिजली परियोजनायें जम्मू-काश्मीर के अन्दर 350 मेगावट बिजली का उत्पादन करती हैं । लेकिन मुझे यह बताते हुए अफसोस है कि इसमें से केवल 22 मेगावाट बिजली जम्मू की कैनाली पावर प्रोजक्ट से पैदा की जाती है और बाकी 328 मेगावट बिजली सारी की सारी वेली की पन-परियोजनाओं से उत्पादित की जाती है । जहां तक बिजली देने का सवाल है, केवल 26 लाख युनिट प्रति दिन जम्मू को दी जाती है जब कि 72 लाख यूनिट प्रति दिन काश्मीर वेली को दी जाती है । जो रेवेन्यू आता है उसके हिसाब में भी बहुत थोड़ा-सा अन्तर है । 11.5 करोड का रेवेन्यू जम्मू इलाके से और 13 करोड़ काश्मीर वेली से आता है । रेवेन्यू में इतना कम अन्तर है, लेकिन जो खर्चा किया जाता है, जितनी बिजली परियोजनायें चल रही हैं उनमें से केवल 10 करोड़ रुपये कैनाली प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है और पांच सौ करोड़ रुपया काश्मीर वेली की परियोजनाओं पर खर्च हुआ है । यह भेदभाव का साक्षात उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है ।

मांग संख्या 12 जो कृषि से संबंधित है, यहां पर भी भेदभाव की बात रखी गई है । जम्मू के अन्दर आरसपूरा के अन्दर एक कृषि कालेज, एग्रीकल्चरल कालेज, चल रहा है चल रहा था । उसे बंद करके काश्मीर के सौपोर में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोल दी गई है और खोलते समय न इलाके की जलवायु का ध्यान रखा गया है और न ही उत्पादन पर ध्यान रखा गया है । आप जानते हैं कि जम्मू बहुफसली इलाका है, मल्टी क्रोप इलाका है, जबकि काश्मीर में केवल एक फसल होती है, पूरे वर्ष में सिंगल क्रोप होती है । मगर एग्रीकल्चरल कालेज काश्मीर में खुला है । जम्मू में चलने वाला कृषि कालेज बन्द कर दिया गया । इसी तरह से आई० सी० ए० आर० के विशेषज्ञों ने जम्मू के लिए सिफारिश की कि वहां एक पशु चिकित्सा विद्यालय, वेटरिनरी कालेज, खोला जाय । लेकिन उनकी सिफारिश को अनदेखी करके वह कालेज भी काश्मीर के अन्दर खोला गया ।

मांग संख्या 16 पब्लिक वर्क्स से संबंधित है । मैं बिलकुल एक नई बात जो बजट से संबंधित है, कह रही हूं । अन्य माननीय सदस्य तो जम्मू-काश्मीर की परिस्थिति की बात करेंगे । मैं बजट के दस्तावेज से बजट की प्रासंगिक चीजों को आपके सामने रख रही हूं । इसलिए कृपया मुझे पांच मिनट का समय दें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्या से मैं कहना चाहूंगा कि यहां हर दल का समय मुकर्रर है, इसलिए मेरे लिए दिक्कत है । आप समय से बहुत आगे बढ़ गई हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अब जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं सिफारिश के तौर पर मांग रही हूं, अधिकार के तौर पर नहीं मांग रही हूं । मुझे मालूम है जो समय दिया गया है । अगर इस प्रकार से बीच में न रोका जाय तो अब

तक तो मैं तीन मांगें रख देती । मांग संख्या 16 जो पब्लिक वर्क्स से संबंधित है उसमें आपने इस बार 28662 लाख 81 हजार रुपये रखे हैं । उसमें सड़क और पुल के ऊपर 3812 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । लेकिन मैं आपको बताती हूं कि पहले सड़क निर्माण पर जो पैसा खर्च हुआ उसमें कितना भेदभाव बरता गया है उसका जब पता चलेगा तभी पता चलेगा कि इस बजट में आगे खर्च किस प्रकार से करवाना है । मैं बहुत प्रासंगिक बात कह रही हूं । सड़क निर्माण के क्षेत्र में 1947 में जम्मू में 1538 किलोमीटर सड़कें बनी हुई थीं । जोकि 1987 में बढ़कर 3500 किलोमीटर हुई हैं । लेकिन कश्मीर में उस समय 748 किलोमीटर सड़कें ही थीं जो अब बढ़कर 4900 किलोमीटर हुई हैं । अगर क्षेत्रों का प्रतिशत निकालें तो जम्मू में 18 फीसदी इलाके में सड़कें हैं जबकि कश्मीर के 40 फीसदी इलाकों में सड़कें हैं ।

मांग संख्या 17 जो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है, इसमें भी भेदभाव की बात आपके सामने कहना चाहती हूं । आज से लगभग दस वर्ष पहले एक मेडिकल कालेज, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के नाम से कश्मीर में खुला था तो वह 50 करोड़ की लागत से खोला गया था, आज से दस साल पहले जबकि रुपये की कीमत ज्यादा थी । लेकिन जम्मू के अंदर मेडिकल कालेज के लिये केवल 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । आप इस सारे बजट को देख लें तो इसमें इस मेडिकल कालेज के लिये एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया है जो कि अधूरा है । इसी तरह से डेंटल कालेज जो जम्मू में खोला जाना था, जिसको जम्मू में खोले जाने की सिफारिश थी वह भी श्रीनगर में खोला गया है । इसी तरह से लिंब सेंटर, कृतिम अंग बनाने का केन्द्र जिसके लिये यहां केन्द्र के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिफारिश की गई थी कि वह जम्मू में खोला जाय वह भी श्रीनगर में खोला गया ।

इसके बाद मैं टूरिज्म की बात करती हूं । मांग संख्या 20.....

श्री वी० नारायणसामी (पांडिचेरी) : दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं ।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया (जम्मू और कश्मीर) : ये जम्मू और कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटकर छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे ।

†[شبیر احمد سلاریہ : یہ جموں اور کشمیر کو تین حصوں میں بانٹ کر چھوڑینگے - ورنہ نہیں چھوڑینگے -]

SHRI V. NARAYANASAMY: She is trying to divide the State. I do not agree with her argument. It is not good for her party. It is going to damage the country's interest.

THE VICE- CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Narayanasamyji, there is the next speaker. You please keep quiet.

श्रीमती सूषमा स्वराज : आप मेरी आखिरी बात सुनिये, तब आपको पता चलेगा । . . . . (**व्यवधान**)

सबसे ज्यादा क्षेत्रीय असंतुलन की बात आप यहां पर करते हैं, नारायणसामी जी । मैं एक ऐसे ही क्षेत्र की बात कर रही हूं और जो बात आपने उठाई है उसी से अपनी बात समाप्त करूंगी, जो अलगाववाद की बात आप उठा रहे हैं । केवल दो मिनट इन मांगों के बारे में सुन लीजिये, उसके बाद मैं इस बात पर आऊंगी । जो आप कह रहे हैं ।

जहां तक टूरिज्म का सवाल है, पर्यटन विभाग का 90 फीसदी पैसा कश्मीर के विकास पर खर्च किया जाता है तथा 10 फीसदी जम्मू के विकास पर जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि 300 फीसदी ज्यादा पर्यटक जम्मू में जाते हैं । 1989–90 के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू में 18 लाख पर्यटक गये जबकि कश्मीर में केवल 6 लाख पर्यटक गये । इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि आपने इसमें जो 2 लाख 198 हजार रुपये रखा है, इसमें से जम्मू के पर्यटन विकास पर आप ज्यादा खर्च करने की बात कीजिये ।

†[ ] **Transliteration in Arabic Script].**

अगली मांग है उच्च शिक्षा के संबंध में। अभी उच्च शिक्षा पर आपने केवल 796 लाख 48 हजार का बजट केवल तकनीकी शिक्षा के लिए रखा है। कुल बजट 3697 लाख 89 हजार है। मुझे दुख है कि गजेंद्र गडकर की रिपोर्ट के बावजूद जम्मू में जो इंजीनियर कालेज खोला जाना था वह आज तक नहीं खुला है। जो पैसा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की मद में रखा है तो मैं चाहूंगी कि कम से कम उस इंजीनियर कालेज को खोलने की तरफ भी ध्यान दिया जाये।

महोदय, अब मैं उस बात पर आती हूं जो अभी श्री नारायणसामी जी ने कही है। इस देश में जहां कहीं भी अलगाववाद की बात उठी है उसमें क्षेत्रीय असंतुलन उसका सबसे बड़ा कारण रहा है। क्षेत्रीय विकास न होना, उसका अंकुरित बीज रहा है। आप जानते हैं कि भले ही आपके बिहार में झारखंड की मांग हो, भले ही उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और उत्तरांचल की मैंग हो, भले ही गोरखालैंड जी मांग हो, जब जब क्षेत्रीय विकास नहीं होता तब तब लोग उठकर अलगाववाद की मांग करते हैं। इसलिये मैं कह रही हूं कि कल ऐसी चीज जम्मू के अंदर भी न आये कि जम्मू के लोग भी यह मांग करने लगे। मैं भारतीय संसद से मांग करती हूं कि आज जो बजट आप भारत संसद के माध्यम से पारित करें उसमें एक यह प्रावधान करिये कि जम्मू और कश्मीर के लिए तीन विकास बोर्डो का गठन करिए। तीन रीजनल विकास बोर्डों में जम्मू विकास बोर्ड, कश्मीर विकास बोर्ड और लद्दाख विकास बोर्ड हों और यह सारा का सारा बजट इन विकास बोर्डो के माध्यम से खर्च करवाये ताकि जो क्षेत्रीय असंतुलन में बजट खर्च होता है वह समाप्त हो, क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हो और जो क्षेत्र अविकसित रह गए हैं वे विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़े। भारत की संसद से पारित किया जाने वाले बजट से यह एक मील का पत्थर साबित होगा।

महोदय, आखिरी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। आज भारत का नन्दनवन कहा जाने वाला कश्मीर, धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर धूधू करके जल रहा है। इसको यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो आप किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति से बाहर आइए और धरती पर निकलकर सच्चाई का सामना करिये। इस तरह की बातें कहकर, चीजों को हटा करके, प्रेसिंग औडर दि कारपेट करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक बात मैं कहना चाहती हूं कि अगर धरती पर खड़े होकर सच्चाई का सामना करेंगे तो स्थिति से निपटने की इच्छा शक्ति आप में पैदा होगी। मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जिस दिन मन में दृढ़ संकल्प ले कर और इच्छा शक्ति को संजोकर आप कश्मीर का मसला सुलझाने के लिए आगे आएंगे आप हम में से किसी को सहयोग और समर्थन में कम नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं जानती हू कि कश्मीर का मसला किसी एक राजनीतिक दल का मसला नहीं है, यह कश्मीर का मसला देश की अखण्डता से जुड़ा हुआ है हम सब का मसला है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): श्री विश्वजित सिंह। एक मिनट रुक जाइये। खाने की व्यवस्था 8 बजे से रूम नम्बर 70 में की गई है। उस में प्रेस के लोग, स्टाफ के लोग और सभी मैम्बर्ज सब के लिए व्यवस्था है। यह सूचना आप लोगों के लिए है।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े-बड़े प्रश्न पूछे गये हैं और बहुत गहरे प्रश्न पूछे हैं माननीया सदस्या ने। वह पूछती हैं कि किस की जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के लिए। हमें तो पता ही है कि कौन जिम्मेदार है। वही शक्तियां जिम्मेदार हैं जिहोंने जब किडनेपिंग हुई थी और वहां श्रीनगर की पुलिस ने जिसने वह आतंकवादी पकड़े थे, उनको छुड़वाया

था, वह सरकार भूल गए आप? पूछा गया है कि किस की जिम्मेदारी है शरणार्थी श्रीनगर वेली छोड़ कर के आ गये, जम्मू की छावनी में गर्मी में, सर्दी में, बुरी हालत में पड़े हैं। किस की जिम्मेदारी है? यह उस सरकार की जिम्मेदारी है, जिन्होंने उनको कहा कि 24 घंटे के अंदर आप यहां से चले जाइए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सब लोग कह रहे हैं और ओपन नोलेज है, पब्लिक नोलेज है। सरकार के जरिए उनको वहां से रात बे-रात, जो लोग वहां से जाना नहीं चाहते थे, कहते थे कि हम यहां बिलकुल ठीक हैं, उनको कहा गया कि हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते हैं आप यहां से चलिये। वह सरकार जिम्मेदार है। पूछा जाता है कि वहां पर कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान के प्रोपेगंडा को प्रोत्साहन दिया गया, पाकिस्तानी करंसी चलती है, पाकिस्तान के झण्डे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान का टाइम लोग अपनी घड़ियों में रख रहे हैं, हिंदुस्तान के झण्डे की, हमारे तिरंगे झण्डे की होली जलाई जाती है। माननीया सदस्या ने कहा है, मैं उसका जवाब देता हूं। यह उन्हीं लोगों की है, इस सब कुछ के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर गोलियां चलाई। जिन्होंने यहां तक कि मौलाना फारुख के फ्यूनरल प्रोसेशन में जाते हुए लोगों पर गोलियां चलाई, जनाजे पर गोलियां चलाई, उस लाश पर गोलियां चलाई, औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर गोलियां चलाई, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आवाम कह रहा है। यह हकीकत की बात है। वह जिम्मेदार हैं। पूछिए और इधर की तरफ देखने से पहले अपने गिरेबान में नजर डाल कर देखिए कि किस तरफ नजर रखनी चाहिए। सोचिये। पूछा जाता है कि यह जो अलगाववादी ताकतें हैं, यह कहां से पैदा हुई हैं।

मैंने जो अभी भाषण सुना है जिसमें बताया जाता है, इतने आंकड़े दिये। अंग्रेजी में एक कहावत है—

"There are lies, there are damn lies and there are statistics."

जो स्टेटिसटिक्स हैं वे तो जो परम का असत्य है उसके भी ऊपर जाकर हैं।

श्री वीरेन जे० शाह: सरकारी दफ्तरों में से।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजित सिंह: मैं सरकारी दफ्तरों की बात कर रहा हूं: ये जो उन्होंने स्टेटिसटिक्स बतायी, यह सरकारी दफ्तरों की स्टेटिसटिक्स बतायी है। अब आंकड़ों को लेकर जिधर भी आप मोड़ देना चाहते हैं वैसा मोड़ दे दीजिए क्योंकि आंकड़े जब निकलते हैं एक पन्ने से तो आप पूरे पन्ने नहीं उठाते। आप इनमें से केवल कुछ आंकड़े उठाते हैं, कोई ऊपर से उठाते हैं कोई नीचे से उठाया कोई बायें से उठाया, कोई दायें से उठाया और वे आंकड़े अपने सामने रखते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह वह सच्चाई है जो आंखों से जाकर देखी जा सकती है।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह: आप बहुत बोलीं, मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा मेरी आप से गुजारिश है कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो यद्यपि आप चुप रहें तो अच्छा रहेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): एक बात तो आप मानेंगी कि आपके लिए ये हिंदी में बोल रहे हैं।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत खुश होता अगर ये भी आंकड़े यहां दिये जाते कि काश्मीर वैली की पापूलेशन जम्मू से कहीं ज्यादा है। यह भी अगर बताया जाता तो बहुत अच्छा रहता। मैं इस बात पर भी बहुत खुश होता अगर बताया जाता कि काश्मीर वैली में जो गरीबी है, गुरबत है वह जम्मू से कहीं ज्यादा है।

[श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह]

हम सब जानते हैं, पर अगर यह बताया जाता तो मैं उससे और भी ज्यादा खुश होता । अगर एरिया की बात करते और बताते तब भी मैं बहुत खुश होता, पर ये बातें, आंकड़े हैं ना, तो आंकड़ों में जब मोड़ देना है और क्यों मोड़ देना है क्योंकि यहां अलगाववाद आता है। यही अलगाववाद डिवाइड एण्ड रूल । ये रूल करना चाहते हैं । तो अभी इन्होंने सिर्फ डिवाइड ही सीखा है । यही है । ये रूल करना चाहते हैं तो डिवाइड सीखा है । अभी डिवाइड करेंगे और सोचते हैं कि कल रूल करेंगे । नहीं, नहीं। ये चाहते हैं जम्मू अलग हो जाए, लद्दाख अलग हो जाए, वैली अलग हो जाए । परंतु यह नहीं होगा । जम्मू और काश्मीर एक है, हिंदुस्तान एक है, भारतवर्ष एक है, एक होकर रहेगा । आप हजारों कोशिशें कर लें, आप लाखों कोशिशें कर लें । आपने जितनी गोलियां चलानी हैं, चला दीजिए, जितने मासूमों को मार दें पर कुछ नहीं होगा । हिंदुस्तान एक ही होगा ।

श्री वीरेन जे० शाह : आप चेयर को कह रहे हैं गोली चलाने के लिए ।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : चेयर की नहीं कह रहा हूं ।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : उस कान्टेक्स्ट में देखिए, जिस कन्टेक्स्ट में बोल रहे है ।

श्री वीरेन जे. शाह : कन्टेक्सट कोई भी हो ।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : ये सब शक्तियांजो है जब ये अपने कारनामें करती हैं तो मैं, ये नहीं सोचतीं कि इनकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी । इनकी कीमत. यह कीमत है कि जो यह बिल इस सदन में आया । यह उन कारनामों की कीमत हम आज दे रहे है । जब हम यह बिल पास कर रहे हैं और जैसा आपने कहा कि रियासत की असेम्बली तो बैठ नहीं रही है । असेम्बली कहां बठे, कैसे बैठ, किन हालातों में बैठे ? असेम्बली तोड़ दी गयी है, भंग हो गयी है, दुबारा इलेक्शन हो नहीं सकते है, जो हालात अभी वहां पैदा हो गये हैं इन्हीं शक्तियों ने, अलगाववादी शक्तियों ने जो हालात पैदा किये है, इन्ही जालिमों ने जो हालात पैदा किये है जब तक ये हालात है । न वहां इलेक्शन हो सकते हैं, न वहां असेंबली हो सकती है और जब तक वहां असेंबली नहीं है तब तक वहां का बजट हम हीं लोग पास करेंगे और कौन करेगा ? यह हमारा काम है उन कारनामों का अंजाम हम भर रहे हैं । वह यह है । मैं आखिरी बात, महोदय,.. **(व्यवधान)**

श्री वीरेन जे. शाह : यह भी बता दीजिए कि फारूक अब्दुल्ला को पहली बार किसने डिसमिस किया था, जिसके लिए बी० के० नेहरू गवर्नर साहब बिल्कुल नाराज थे, फिर भी ?

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : श्रीमान निकरधारी मैं आपसे गुजारिश करूंगा... **(व्यवधान)**

श्री वीरेन जे० शाह : हम जो पहनकर आए हैं, इसको आपकी जबान में निकर कहते हैं? ... **(व्यवधान)**

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : मैं आपके बाहर के लिबास पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपके मानसिक लिबास की बात कर रहा हूं । आपने बाहर तो तंग-चुस्त पायजामा पहन रखा है, पर आपका मन अभी भी निकरधारी है । महोदय, अंत में, मैं ज्यादा इस सदन का समय नहीं लेना चाहता, सब लोग भोजन के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं... **(व्यवधान)**

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है । ... **(व्यवधान)** आप ऐसी बात मत करो, हम आपको सुनेंगे ।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह :: अच्छा, सुनेंगे। चलिए, ठीक है। . . . (व्यवधान) सुनेंगे तो सुनिए। . . . (व्यवधान) बहुत कुछ हमेशा जम्मू-कश्मीर के बारे में कहा जाता है, धारा 370 के बारे में कहा जाता है और वह पार्टी जिसकी सदस्या अभी जोर-जोर से सवाल कर रही थीं वही पार्टी हमेशा कहती है कि इस काश्मीर की समस्या का समाधान केवल एक ही है और वह हमेशा कहते हैं कि संविधान की धारा 370 को वापस ले लीजिए और सब खत्म हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं या नहीं, क्यों बहन जी बताइये ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : कहते हैं।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : क्यों भाई साहब आप भी बतायेंगे ? . . . (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : (उत्तर प्रदेश) : : धारा 370 जब खत्म हो जाएगी तो अलग हो जाएगा और समाधान हो जाएगा। . . (व्यवधान)

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : वह तो आप समझते हैं, मैं समझता हूं और यह लोग नहीं समझते हैं। यह अपनी बात करते हुए हमेशा करते हैं कि संविधान सभी में यह सब कुछ हुआ था। और कांस्टीटयूएंट असेंबली में यहां तक कहते हैं कि एक मौलाना हजरत मोहनी ने कहा था कि धारा 370 मत लागू करो। कहते हैं या नहीं कहते हैं ? हमेशा कहते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : संविधान उठाकर देखें कि संविधान क्या कहता है ?

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : मैं आपको सुनाता हूं। . . (व्यवधान) मैं आपको सुनाता हूं। आप सुनिए जरा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे पूछ रहे हैं कि आप कहती हैं या नहीं कहती हैं, जवाब दें ?

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : हां।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कंस्टीटुएंट असेंबली का अपना संविधान उठाकर देखो कि उसमें कहां लिखा है। उसमें आप देखिए।

SHRI VISHVJIT P. SINGH: The Constitutional position, Mr. Vice-Chairman, is that according to the Constitution at that time, these temporary provisions were made with the intention of allowing the populace of the princely States to decide what kind of a constitutional set-up they wanted. This was a contract of the Indian States. And the people of the States. And the pepole of the Princely States elected their Constituent Assemblies or Assemblies which then decided on the form of the Constitution. And let me tell this hon. House, Mr. Vice-Chairman, that the various Princely States sat themselves up as Constituent Assemblies and adopted. (*Time bell rings*). I am just finishing, Sir. In the State of Jammu and Kashmir, there was a very delicate situation which was there because of the problem with the Maharajah. The popula-

8.00 P.M.

on was totally with the Government of India. The population decided, the Assembly decided, on a separate Constitution for the State of Jammu and Kashmir, merging it with India and lin[illegible] to section 370. If you rem[illegible]ion 370, the constitutional position is that the amalgamation of the J&K State with the Union of India lapses from that moment. And that is what my friends on the Opposition understand.

SHRI JAGESH DESAI: They know it.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: They know it. Even these people know it. But they do not want it and they want it. That is the difference. I may quote, Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): But [illegible] also conclude now.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: I am going to conclude. I am quoting Shri Gopalswamy Aiyangar. This is the Constituent Assembly debate dated 17th October, 1949:

[Shri Vishvjit P. Singh]

"The effect of this article is that the Jammu and Kashmir State which is now a part of India will continue to be a part of India, will be a unit of the future Federal Reublic of India, and the Union Legislature will get jurisdiction to enact laws on matters specified...", etc. etc.

"And steps have to be taken for the purpose of convening of the State Assembly. When it will come to a decision on the different matters, it will make a recommendation to the President who will either abrogate the article or direct that it shall apply with such modifications and exceptions as the State Assembly may recommend. That, Sir, briefly is the description of this article."

Sir, the State Assembly directed that this the article be retained in the Constitution of India. This is now no longer a provision which is a temporary provision, because it is only from this that we get the union of the State of Jammu and Kashmir with the Union of India.

श्रीमती सुषमा स्वराज : कांस्टीटयूशन में 370 के लिखते ही लिखा है । ... **(व्यवधान)**

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : : इसमें "इस" कर के लिखा है ।

At that time it was a temporary provision.

जब आप यह भी नहीं समझती तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सोचने की बुद्धि तो ईश्वर ने केवल आपको ही दे रखी है । पूरी संसद में सोचने की ठेकेदारी सिर्फ आपकी है ।

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : नहीं-नहीं, मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है । I am not a contractor. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिए आप दोनों सदन के माननीय बुद्धिमान सदस्य है । मैं अनुरोध करूंगा कि समय की रक्षा करते हुए अब आप अपना भाषण समाप्त करें

श्री विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह : माननीय सदस्या समझदार हैं । मैं समझता हूं कि किसी को भी जब कडवे सत्य का सामना करना पडता है तो उसको न वह पहचानना चाहते हैं और न उसको समझना चाहते हैं । मैं पूरी तरह इस बात से वाकिफ हूं ।

श्री वीरेन जे० शाह : कडवा सत्य है, लेकिन सत्य शब्द की व्याख्या फिर से करनी पडेगी आपके लिए ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह: ठीक है, ये लोग मेरे भाषण के बीच में जब बोलते हैं तो जितना ये बोलते हैं, मैं उतना ही सत्य बोल रहा हूं । **(धन्यवाद)**

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

There are a very large number of aspects of the Kashmir problem which need to be gone into. In the first instance, I would confine myself to the Budget and the implications of it. A mere glance at it will make it very clear that the State of Jammu and Kashmir is heavily dependent upon the Union finances. Those who talk of pre-1952 position or 1947 position, how unrealistic they are? In 1947-48 the total budget of Jammu and Kashmir was Rs. 4.18 crores. Now we are having about 350 times more than what it was. Practically the entire plan expenditure comes from the Union finances. Quite a lot of non-plan expenditure also comes from the Union finances. For instance, in the Seventh Five Year Plan Rs. 18.38 crores was given by the Union Government to this State. The

scale of the financial aid is very liberal whereas the population of Jammu and Kashmir is 0.8 per cent of the total population of the country. It has been getting on an average 2.7 per cent of the financial allocations of the country. Whereas the per capita expenditure in West Bengal is Rs. 67—this is the figure of 1989—in Bihar, per capita expenditure was Rs. 109, in Assam Rs. 440 and in Kashmir it was Rs. 1122. These figures are population-wise. You can imagine how much aid has been provided liberally. When we say take us back to the position of 1953 or when we want to be independent what would we see? The facts of geography, the facts of defence, the facts of practical considerations all are against it.

Now, it is very clear that the financial base of the State is very weak. The economic base of the State is very weak. But whatever amount you have been sending, how is it utilised? That is the issue. When my brother was speaking about Article 370, the issue is abrogation or retention of Article 370. That is usually talked about. But nobody talks about its misuse. For instance, already the financial base of the State is very weak. Why there is no wealth tax in Kashmir, and why there is no Urban Land Ceiling Act in Kashmir? Why there is no fift tax in Kashmir? Why? This is the issue which we should consider. Why this Article 370 is used to obstruct healthy financial legislation in the State? Was it meant for this purpose that we should create a corrupt and callous oilgarchy there? It will serve a particular group whether they are in politics or in administration or in business. This is the point which the nation has to consider. After so much money has gone there, why the visible results are not there? I will give you two instances. Now you have got the Urban Land Ceiling Act and Wealth Tax Act; you may not get money out of it, but somebody will have to declare how much land he is holding and how much wealth he has, somebody has to declare. That is the reason why legislation is not done in Kashmir. Therefore, kindly go to the real issues of Kashmir. With due respect, I find the real issues are not known to this House.

Now, let me say something about land resources. Somewhere when you want to have a hotel site, you will sell it by auction because it is a commercial project. You want that the auction should be on all-India level and let somebody, compete with it. In Jammu and Kashmir, under the protective wall of Article 370, land is allotted for a song to some favourites and the favourites then go to the Bombay party with some sort of profit agreement and then he gets it sanctioned. Thus the intermediary makes all the money. I do not want to refer to my book; but I have given all the details and let the Finance Minister look into this. The hotel site which is given to a particular party for Rs. 18,000 or Rs. 20,000 on lease, is offered to a Bombay party by that person on Rs. 40,000 annual lease, and I have calculated that in a 99-year lease, the intermediary will gain Rs. 18 to 20 crores. What is this? If we put this plot to auction, who is going to benefit? It is the poor Kashmiri who will benefit because somebody will construct a hotel, people there will get employment, and local people will get all the facilities. But it only the intermediary who is getting all the benefits and setting the whole circle in motion where black money comes in and exploitation comes in, and all this is because of the propaganda for retention of article 370. It is to hide those parties, it is to hide the corruption there that article 370 is used.

I will give you another instance. On the Dal Lake you create all types of hotels. The steamer froze there in the Dal Lake and you destroyed the Dal Lake; you destroyed the environment; you destroy this way Kashmir for ever. If the Indian environment Act is introduced there also, whom will it serve? Will it serve the Kashmiris or somebody else?

[Shri Jagmohan]

This is also an instance where article 370 is used or misused.

We had the anti-defection law in India. Why was it not introduced there in Kashmir? There, another law was introduced whereby the party chief will decide whether a person had defected or not. The party chief will decide who has revolted against him. He will sit over judgement; he will be the Chief Minister and he will be recommending Ministers, and he will decide whether somebody has revolted against him or not. So, we should understand what for these laws are being kept separate. A type of feeling is being created that article 370 is doing this or that for the people. In fact, abrogration of article 370 is in the interest of Kashmiris. It is in the interest of poor Kashmiris. Maybe, it is not in the interest of the elite class, and that is why that interest has seen to it that a permanent opinion is created against India, against the Union by a false propaganda.

I will tell you another aspect. The fundamental purpose of a government is justice. Once we deviate from that central objective, we always land ourselves in confusion. Mrs. Swaraj was talking about allocations to the medical college or this college or the other. I do not want to get into the intricacies, whatever be the right or wrong. But I will give you one instance. A Kashmiri student is in a medical college. She has passed her MBBS examination. Then she applies for getting into MD course; but she is refused. What is the reason given? The reason is, she has married an Indian citizen. Can you imagine a situation like this? She is asked to produce a certificate. She is a permanent resident of India, a citizen of India also and she is denied. You can see that case in my book; I have given details. There is a writ petition filed by her that she has been denied because she married an Indian citizen. With Union finance a medical college is opened, and in that medical college you cannot get admission because you have married an Indian citizen. Can there be a worse situation than this?

Take the case of West Pakistan refugees who came in 1947. They did not come to see Kashmir; they were not on holiday. They came to Kashmir because there was partition; there were riots; there was trouble, and these people came to settle there. About 12,000 families are there. And uptil this time, they have not been given citizenship rights. There children cannot go to the medical college. Their children cannot get admission in any agricultural college. They cannot get admission in any of the professional colleges. They cannot become members of the co-operative societies. They cannot vote for the Assembly. But we are a nation who go and fight for the rights of the South African people. And here is a nation where a child born there is subjected to so many disabilities—Article 370 and its corollary, Constitution and the Citizenship rights. The issue is of justice. Are we a modern nation? What are we doing? Are we acting in a primitive manner? These are the few things which you should kindly bear in mind. You have rung the bell and I do not want to take much time. There are many things which I have to say. I think it is highly superficial to look for the roots of the Kashmir problem in the last two years, three years, five years or six years. The roots of the Kashmir problem lie deep. You will be surprised to see that they lie in the permissive attitude and soft attitude; they lie in the policy of deception and duplicity; they lie in corruption; they lie in the administrative infirmities and they lie in the spurious democracy. On Page 152 of my book, I have given a sample of the posters. At every election time, the propoganda is "all rivers go to Pakistan, but all the salt comes from Pakistan, etc." When the motive issues are raised, the younger generation of Kashmir has been fed on such slogans. There have never been any

elections by performance, but only on an anti-India campaign. And this has resulted in all these problems. For the last 44 years, we have told the young Kashmiris that India is our enemy. Whom do you blame now? We cannot blame the young people. You see all the evidence that I have given in 4400 pages and I will request all the Members of Parliament to go through that because it is all documented. It is all listed. Kindly go through that book. I do not want that you should take a particular view or you should not take a particular view. It is in the interests of the nation as a whole and it is not a question of one particular party or the other.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): Give one complimentary copy to every Member.

SHRI JAGMOHAN: I suggest, you go to the libarary and read it. If I am referring to it. I am not referring to it because I want to sell my book. I don't want to sell my product. I have donated it for charity.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You are provoking people to buy your book and read it. Who is going to buy the book? Who is going to read the rubbish?

SHRI JAGMOHAN: I will explain it to you. I do not want to refer, since you have rung the bell ... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: When you were in power, you should have done somsthing. Now, you are coming and blaming... (*Interruptions*) You are preaching sermon... (*Interruptions*)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मदन के एक सदस्य हैं डा० जे० के० जैन, वह अपनी कैसिट बेचते थे और यह अपनी किताब बेचने लगे।

SHRI V. NARAYANASAMY: You are talking about corruption now. What did you do when you were the administrator?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Please Mr. Narayanasamy...

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी: यह होगा कि वह देश के संविधान की किताब बेचते हैं।

† [مولانا عبیداللہ خاں اعظمی : یہ ہوگا کہ وہ دیش کے سنودھان کی کتاب بیچتے ھیں -]

SHRI R. K. DHAWAN: (Andhra Pradesh): During Rajiv Gandhi's period, he wanted to continue as the Governer of Kashmir, when he was asked to resign after his term was over. If this was the situation, why did he want to continue? (*Interruptions*)

SHRI JAGMOHAN: Mr. Dhawan, I will answer you ... (*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Dhawan, I request you to take your seat.

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): I have a point of order.

SHRI V. NARAYANASAMY: Now he is preaching sermon.

SHRI R. K. DHAWAN: When Shri Rajiv Gandhi sent a letter to him asking him to resign when his term expired, he wanted to continue. Why did he want to continue? ... (*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Dhawan, please take your seat.

DR. NAGEN SAIKIA: I have a point of order.

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Mediators were brought from outside to Kashmir. They are cutting the fate of the Kashmiri people. What is going on there?... (*Interruptions*)

DR. NAGEN SAIKIA: Sir, I am on a point of order... (*Interruptions*)

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Jagmohan, please sit down .Dr. Saikia is on a point of order.

DR. NAGEN SAIKIA: Sir, Mr. Jagmohan is making some important points in relation to the Kashmir problem. I do not think Mr. Dhawan's point about his continuance in office as Governor of Jammu and Kashmir has any relevance. It is not relevant at all. (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: How do you say that? It is relevant. (*Interruptions*)

SHRI R. K. DHAWAN: If he was not satisfied with the situation, why did he want to continue? (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: If he was an upright person, he should have quit, he should have resigned. But he continued for the full term and now he is accusing the Government. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Shankar Dayal Singh): All of you, please take your seat. (*Interruptions*) Mr. Jagmohan, you also please conclude. (*Interruptions*)

SHRI R. K. DHAWAN: Let him deny that. Let him deny that he did not want to continue. Let it go on on record. (*Interruptions*)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप बैठ जाइए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : गवर्नर होने के बाद . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप जगमोहन जी के भाषण को समाप्त होने दीजिए । बीच में मैं किसी को एलाऊ नहीं कर रहा हूं । माथुर साहब आपको या धवन जी, किसी को एलाऊ नहीं कर रहा हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: गलत बात है . . . (**व्यवधान**)

श्री आर० के० धवन: मैं इनके बारे में बता रहा हूं । जब इनका टैन्योर खत्म हो रहा था तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया . . . (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Dhawan, Mr. Mathur and Dr. Saikia, please take your seat. Let Mr. Jagmohan finish his speech. (*Interruptions*)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Sir, you can give my time to Mr. Jagmohan. (*Interruption*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Jagmohan, please conclude. There is no question of any provocation.

SHRI JAGMOHAN: The only point I would like to emphasise again is this. I did not want to refer to anything. Since you said that the time is short, I said that those who are interested can go through it. I had no intention of saying that you should buy my book. I have donated the royalty on the book for charity. I would still like to appeal that you should go through it. (*Interruptions*)

SHRI R. K. DHAWAN: What about the royalty on that book? How was it written? How was it sold: Say that also. You say that you have donated the royalty on the book for charity. You are so magnanimous! What about the earlier royalty? (*Interruptions*)

SHRI JAGMOHAN: I deny Mr Dhawan's point in regard to my continuance. The issue was whether should continue, or, I should fight elections. I said 'politics is not my cup of tea', that I would not like to fight elections. Let me correct it. Let me state the fact. The third thing is..

SHRI R. K. DHAWAN: Therefore, you wanted to continue as Governor.

SHRI JAGMOHAN: I did not say that. (*Interruptions*)

SHRI R. K. DHAWAN: You rang me up twice. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Dhawan, please sit down. (*Interruptions*)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं इतना जानता हूं सदन में इस प्रकार का झगड़ा नहीं किया जाना चाहिए . . (व्यवधान) हम सब जानते हैं आपने क्या-क्या किया है, क्या-क्या धंधे किए हैं . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माथुर साहब आप बैठिए । जगमोहन आप समाप्त, कीजिए

SHRI JAGMOHAN: I am sorry. I will stop it. All that I say is that, a lot of disinformation has been spread. That is the truth. Truth is bitter and, therefore, it is difficult to swallow. (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Sir, Mr. Jagmohan was talking about mediators from other parts of the country. He was the person who brought mediators from outside. I know personally. I had gone to Kashmir. I investigated. When he was Governor, during the Congress regime,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Afzal, please sit down. I am calling the next speaker. Shri Ranjit Singh. (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: He took mediators from all over the country and compelled the Kashmiris ... (*Interruptions*)

SHRI JAGMOHAN: What he is saying here, he should say it outside the House. I challenge him to say it outside the House. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Shri Ranjit Singh. (*Interruptions*). Now the next speaker is Shri Ranjit Singh.

श्री रणजीत सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय मैं . . . (**व्यवधान**)

SHRI VISHVJIT P. SINGT: I may mention, Sir, a threat has been issued to one of our Members. I agree, he is not a Member of my party but I still have some respect for him. He is an hon. Member of this House and he has been threatened that "I challenge you to come out and repeat it." May I say as a counter that every single allegation that is levelled in this House is leveled outside this House. Do, whatever you can.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदय, इन्होंने चैलेंज किया है, माइनोरिटी कम्यूनिटी के सदस्य को इन्होंने धमकी दी है । इन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए . . . (**व्यवधान**)

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : माइनोरिटी के लोगों को धमकी देना इनका काम है (व्यवधान)

† [مولانا عبید اللہ خاں اعظمی : مائناریٹی کے لوگوں کو دھمکی دینا انکا کام ہے - .. (مداخلت) . . .]

श्री राम नरेश यादव : इन्होंने जो कहा है वह प्रोसीडिंग में से निकाल दीजिए । . . . (**व्यवधान**)

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: It should be on the record. It shows these facts.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): आप बैठिए । (**व्यवधान**)

†Transliteration in Arabic Script.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इन्होंने अपनी असली पहचान बता दी। ये अपने शब्द वापस लें ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ठीक है, आप बैठिए तो। मैं बताता हूं। मैं जब खड़ा हूं तो आप बैठिए। आपके शोर शराबे में मैं ठीक से सुन नहीं सका कि माननीय सदस्य श्री जगमोहन ने क्या कहा। रेकार्ड से हटाने से मैं समझता हूं ...(**व्यवधान**) हमारा यह कहना था कि रेकार्ड से हटाने से कोई बात उतनी नहीं बनती है जितनी आदमी के दिल में यह बात नहीं उठनी चाहिए मैं माननीय सदस्य श्री जगमोहन जी से यह अनुरोध करूंगा कि उन्होंने क्या कहा था? यदि उन्होंने यह बात कही थी तो उनको दुख प्रकट करना चाहिए ... (**व्यवधान**)

श्री जगमोहन : जब इन्होंने आरोप लगाया था तो ने कहा था कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह गलत है। तो मैंने जरूर कहा था कि यही बात बाहर कहिए। अगर यह आप मुनासिब. नहीं समझते तो मैं इसको ड्रोप करता हूं। ...(**व्यवधान**) मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि जो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, यह गलत है।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): You have to apologise for the same. We will not accept this. On the floor of the House you cannot say this. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Please take your seat first.

SHRI JAGMOHAN: I have said, Sir. If you think it is improper I withdraw it.

श्री रणजीत सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर के बजट पर इस सदन में चर्चा हो रही है और उसको पास करने के लिए यहां सभी आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं समझता हूं कि हम एक ट्रबल्ड स्टेट की बात कर रहे हैं। उसका बिल पास करने में सम्मानित सदन में ही ट्रबल पैदा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह सभी के लिए अफसोस की बात है। सभी पार्टियों के लीडर साहबान यहां पर बैठे हैं। मेरा निवेदन है कि इस सदन की बाहर बहुत इज्जत है। इस सदन में आने से पहले मैं समझता हूं कि 80 परसेंट लोग ऐसे हैं जो एसेंब्लीज से निकलकर आते हैं।

[**उपसभाध्यक्ष** (श्री **भास्कर अन्नाजी मासोदकर**) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम आए तो यह समझते थे कि यहां बचत अच्छे लोग हैं एजुकेशनिस्ट हैं, विद्वान हैं जुरिस्ट, लोग हैं।

मैंने थोडी सी बात इस लिए कही कि कई बार ऐसा देखने को मिला है। मैं जो अपनी बात शुरू करना चाह रहा था वह यह कहा रहा था कि मेरे से पहले सुषमा स्वराज जी ने जिक्र किया कि यह बिल हम पास करने के लिए बैठे हैं। इससे पहले पंजाब का किया, फिर एक्सटशन का किया। पंजाब में प्रेजीडेंट रूल एक्सटेंट करने के लिए हमें पास करना पडा। फिर यह बिल पास करने के लिए हाउस को एक्सटेंड करना पड़ता हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर जैसा पंजाब के लिए, कश्मीर के लिए किया, अगर यही हालत असम में हो गई या दूसरे स्टेटों में हो गई तो कहीं सदन का काम यहीं न रह जाए। कहीं यही बिल पास करने का काम इस सदन का न रह जाय। मेरा आपके माध्यम से वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन हैं कि कश्मीर की सही प्रोब्लम क्या हैं उसको देखना चाहिए। बिल अभी भी पास हो जाएगा, यह कोई बडी बात नहीं है। यह लीगल कन्स्टीट्यूशनल फार्मल्टीज हैं जो पूरी की जा रही हैं। मेरा यह निवेदन हैं कि कश्मीर की हालत इतनी खराब है कि उसे ठीक किया जाना जरूरी हैं। अगर हालत ठीक होते हैं तो फिर सारे देश

के लिए, सभी पार्टियों के लिए हित की बात है। हम राजनीति की बात बाहर करें, अपने मंच पर बात करें, पर जब हम यहां बैठे हैं तो हम पर राजनीतिक इल्जाम लगते हैं। इसलिए हमें यहां बड़ी ईमानदारी से, रिस्पोंसिबिलिटी से सारी बात कहनी चाहिए।

मैं जिक्र करूंगा कि जम्मू-कश्मीर में सब कुछ हम दे रहे हैं। वहां सब स्टेटों से ज्यादा प्राथमिकता देकर सब बातें की जा रही हैं। उसके बाद भी कश्मीर की हालत ऐसी क्यों है? जैसा मेरे से पहले हमारे सी०पी०एम० के माननीय सदस्य ने कहा सभी पार्टीज के दफ्तर आज कश्मीर में नहीं हैं। कोई राजनीतिक पार्टी वहां अपना आफिस नहीं चला सकती। कोई भी जिम्मेदार आदमी आज कश्मीर वैली में नहीं रह सकता। यह देश की हालत है। इन हालात में मैं समझता हूं। सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उन हालात को दुरुस्त किया जाए। मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि कश्मीर और जम्मू रीजन में जो बातें चली हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट खड़े हैं और कुछ उसके प्रो खड़े हैं। कुछ फैक्टस मैंने लिए हैं, कुछ बुक्स से हैं, पेपर से हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर में इतना कुछ होने के बावजूद भी वहां ऐसे हालात क्यों हैं। मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि 27 अक्टूबर, 1947 को जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनी थी, हरि सिंह जो वहां के महाराजा थे उनसे यह फैसला हो गया था। जैसे और स्टेटों ने अपने आप को इसमें मर्जर कर लिया था, कश्मीर का भी हो गया था। उसके बाद शेख अब्दुल्ला वहां प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, एक डैमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनी थी, चुनी हुई सरकार बनी थी। नेशनल कान्फ्रेंस की बनी थी। उसके बाद इंदिरा जी के वक्त एक समझौता हुआ था। इस समझौते में शेख साहब ने सब कुछ लिख दिया था जो भारत सरकार ने चाहा। उस समझौते में प्राइम मिनिस्टर का आफिस भी खत्म कर दिया गया था, सदरे रियासत का आफिस भी खत्म कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का आफिस बना दिया गया था। मैं समझता हूं इससे ज्यादा नेशनल गवर्नमेंट किसी स्टेट के हक में कोई ऐसा समझौता नहीं कर सकती थी। उसके बाद भी हालात ऐसे बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि इसके कुछ कारण और हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई यह कहे कि कश्मीर के लोगों में इस देश के लिए प्रेट्रेटिज्म नहीं है, मैं इस बात को गलत मानता हूं। 1965 की लड़ाई जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच हुई थी सारा कश्मीर हमारी फौजों के पीछे खड़ा था। किसी कश्मीरी ने कोई गद्दारी नहीं की थी, चाहे वैली का आदमी हो या जम्मू का आदमी हो। जो तारीफ की बात है वह करनी चाहिए। इसके कारण जो हैं वे पालिटिकल हैं। इसके लिए कौन रिस्पोंसिबल हैं सब जानते हैं। जो पार्टीज थीं, जो हुक्मरान थे उन्होंने कभी भी लोगों को राज करने का मौका नहीं दिया। इलैक्शन हुए तो रैगिंग हुई, चाहे नैशनल कांफ्रेंस की गवर्नमेंट थी या दूसरी गवर्नमेंट थी। जब भी इलैक्शन हुए तो एक तरफा इलैक्शन होते गए। लोगों को यह लगा कि हमें डिसीव किया जा रहा है। पढ़े-लिख यूथ सड़कों पर आ गए। 1987 में फारूख अब्दुल्ला की सरकार बनी, कांग्रेस के साथ मिल कर सरकार बनी। उस वक्त गवर्नर की जो रिपोर्ट थी वह आपने भी पढ़ी हैं और मैंने भी पढ़ी हैं। मैं उस पर ज्यादा लम्बा नहीं कह कर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर की रिपोर्ट में यह भी था कि हालत ऐसे हैं कश्मीर ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद फिर फारूख अब्दुल्ला हटा दिए गए। उसके बाद वह यहां से यूरोप चले गए इलाज के बहाने से। उसके बाद जब प्रेस के लोग उनसे मिलते हैं तो जो एक सेंटेंस उन्होंने कहा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि फारूख साहब कश्मीर के क्या हाल हैं तो उन्होंने कहा

[श्री रणजीत सिंह]

He replied:

"I am a useless person. I play golf."

This was the sentence which the Chief Minister uttered to the Press people.

मेरे कहने का मतलब यह है कि वह भी ऐसे ही करते रहे । कश्मीर जिस तरीके से दूसरे स्टेटों में डिस्पोरिटी रखी गई है उसका फर्क, जब हर आदमी पढता है, समझता है और बुक्स में जाता है, डिटेल्स देखता है, आंकडों को देखता है, तो उस पर असर पड़ता है और राज्यों पर भी असर पडता है । मेरे से पहले उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जम्मू में 30 सीटस हैं, कश्मीर में 43 हैं और लद्दाख में दो सीटस हैं । पापुलेशन के हिसाब से जम्मू में 74 हजार 113 पर एक एम ए । ए बनता है, कश्मीर में 72 हजार एक बनता है और लोक सभा के लिए जम्मू में 13 लाख 47 हजार 810 पोंपुलेशन पर एक एम-पी० बनता है और काश्मीर में 10 लाख 13 हजार 367 पर बनता है । 76 वर्ग मील की जो बात है, मैं समझता हूं कि 5447 वर्ग मील जो एरिया है वह जम्मू का है और काश्मीर का 3 हजार वर्ग मील है । काश्मीर राज्य की आबादी देश की आबादी का सिर्फ 0.1 परसेंट है जब कि सहायता जो केंद्रीय सरकार करती है, वह 2.57 भाग है जो इस राज्य को दिया जाता है। 1989-90 में प्रति व्यक्ति गवर्नमेंट इंडिया ने जो मदद की है वह काश्मीर के लिए 1122 रुपये थी, बिहार के लिए 101 रुपए है, यू०पी० के लिए 91 रुपए है, वैस्ट बंगाल के लिए 67 रुपए है । केंद्रीय सरकार जो पैसा देती है उसका 90 परसेंट ग्रांट के रूप में दिया जाता है, 10 परसेंट एज लोन काश्मीर को दिया जाता है । इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना फेवर दुनिया में कोई देश अपने किसी स्टेट को नहीं करता है , इस तरीके से कोई देश नहीं करता है । 1947-48 में राज्य का कुल बजट 4.81 करोड़ रुपयों का था 1989-90 में यह 1237 करोड़ का हो गया है । प्रति व्यक्ति जो वेलफेयर के लिए वहां पैसा खर्च किया जा रहा है 1947-48 में 15 रुपए था और 1989-90 में वह 145 रुपए हो गया । इतना सब करने के बाद भी वहां हालात क्यों बिगडे हैं । उसके लिए जो कारण हैं उनका मैं ब्रीफ में जिक्र करूंगा । वहां पर गवर्नमेंट को ठीक तरीके से न चलाने से, लोगों को कंफिडेन्स में न रखने से, प्रशासन का लोगों को विश्वास में न लेने की वजह से सारा कुछ हुआ है । सैन्टर ने आज तक काश्मीर को एक कालोनी की तरह से ट्रीट किया है । कभी भी दूसरी स्टेटों की तरह से स्टेट मानकर गवर्नमेंट मानकर आज तक ट्रीट नहीं किया । दूसरा मैं आप से यह भी जिक्र करूंगा कि हर जगह कुछ झगडा होता है । साउथ अमेरिका में भी दो स्टेटों हैं जिनमें एक आलाबामा है और दूसरी मिसीसिपी स्टेट है' इन दोनों ने अलग होने के लिए रिवोल्ट किया । लेकिन बाद में सबसाइड हो गए । उसके बाद इनकी चर्चा नहीं होती है लेकिन हमारा कश्मीर बराबर प्रोबल्मस बना हुआ है । मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि जिस तरीके से वहां पर माइग्रेशन हुआ है और लार्ज स्केल पर हुआ है और सबसे ज्यादा मैं समझता हुं कि दिल्ली में और उसके बाद जम्मू में लोग आए हैं । बडे अफसोस की बात है कि एक स्वतंत्र देश में अपने नागरिक अपने देश में अपने घर द्वार सुरक्षा के कारण छोडने के लिए विवस हुए । यह हमारे लिए सोचने की बात है । इस प्रोबलम को सोल्व करने के लिए दो बातें कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा ।

How the problem is handled will have a significant implication on the national scenario. I request that those persons, discredited leaders, local as well as Central, should be excluded from decision making.

यह वहां सबसे बड़ा कारण रहा है जिसका लोगों में कभी विश्वास नहीं रहा । तीसरी बात यह है कि वहां पर जो रीजन्स की बात है, कभी लद्दाख की बात की जाती है, कभी कश्मीर की बात चलती है और कभी जम्मू की बात की चलती है और मुझ से पहले किसी माननीय सदस्या ने कहा कि

पैसा कहीं कम बांटा जाता है और कहीं ज्यादा बांटा जाता है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप पैसा इस तरीके से बांटे कि वह डिस्ट्रिक्टस में जाए, चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, तहसील और ब्लाक लेवल पर सब लोगों को बराबर की हिस्सेदारी से पैसा बांटा जाय । क्योंकि बहुत सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Kashmir was a heaven on Earth. That was an old saying. Kashmir is a hell on Earth. That is a new saying. Who is responsible for this? It is the Congress Government which is responsible for this. It is the Congress Government which had dethroned Farooq Abdullah, which is responsible for this. A blunder which was committed on that day has become a curse to the nation today. Nevertheless let the bygones be bygones. All of us should unitedly fight to solve the problem. It is very unfortunate and improper to discuss the Budget of Jammu and Kashmir in this House again and again every six months. By this the people of Jammu and Kashmir have been driven away from the mainstream. So, my first demand is that there should be a popular Government there. There should be a democratically elected Government there. Therefore, elections should be held there as early as possible.

The Government should control terrorism and kidnappings there with an iron hand. Security should be tightened on the border areas and the Government should take proper steps to stop migration. Refugees should be rehabilitated properly.

Tourism is the backbone of Jammu and Kashmir. Unless tourism is projected and improved, the economy of Jammu and Kashmir will not improve. So, proper steps should be taken to protect and promote tourism in Jammu and Kashmir. Similarly, business of fruits and dry fruits is also one of the major sources of income in Jammu and Kashmir. That should also be protected and promoted. Jammu and Kashmir is a big State with large hilly areas. Its roads are very poor. Its communication system should be improved. The Parliament and the nation should send a message to the people of Jammu and Kashmir that 80 crores of Indians are their brothers and sisters. That message should be sent to the people of Jammu and Kashmir. I hope and trust the next budget of Jammu and Kashmir would be discussed and passed in the State of Jammu and Kashmir. With these words I conclude.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: I think from Jammu and Kashmir this unfortunate position has developed that I and Mr. Amla are the only Members in this House. Amla Sahib may not like to speak, but I will say some words with reference to the Bill, which has been brought forward.

SHRI TIRATH RAM AMLA (Jammu and Kashmir): Reasons are known to you.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Yes. I know the reasons very well.

My first submission before your honour is this. It has been stated that in Jammu and Kashmir Article 370 is the root cause of the trouble and that it should be done away with. This is one view projected by Mr. Jagmohan and also by the BJP Mr. Jagmohan's contention is that by virtue of this Article 370, the wealth-tax does not apply to Jammu and Kashmir. This is one of the reasons, according to him The Wealth-tax, as applicable in India, was applied in Jammu and Kashmir by the Government of Jammu and Kashmir The matter went to the High Court. The High Court said that in accordance

[Shri Shabbir Ahmed Salaria]

with the provisions, the Constitutional settlement and the division of powers with the Central Government and the Jammu and Kashmir, it would not apply. The State of Jammu and Kashmir went in appeal to the Supreme Court and the appeal is pending there. Next he said that in Dal Lake the hotels are adjoining one another and the sewage water is getting into the Lake. What has this to do with Article 370? If somebody does something improper and lets it go into the Dal Lake, the law enforcing agencies will take care of it. It has nothing to do with Article 370. The State has got its own Act on environment and on such pollution matters, the law can take its course.

Thirdly, Mr. Jagmohan said that in Jammu and Kashmir, there are people who take land on lease and then enter into an agreement with somebody in Bombay and get money out of it. What has article 370 got to do with this? Such things take place in many States. People get land, then, they enter into a transaction with a hotel running company and in that transaction they may make money. What has Jammu and Kashmir got to do with it? On the other hand, the Land Grants Act is enforced in Jammu and Kashmir which says that irrespective of the area to which anybody belongs in the country, he can take a lease of land for 99 years in Jammu and Kashmir which was not permissible under the Maharaja. In Mizoram, in Nagaland, in Himachal Pradesh and in so many States, there are laws which are meant to protect the local people and the local interests. But such a law if it exists in Jammu and Kashmir with 99 years' lease how is it possible for any person outside the State to own it? How is it bad? Therefore, his reasoning was that this is the wrong thing there because of article 370.

If some people in politics have been acting wrongly or making money, as he assumed, he says that it is due to article 370. It is strange enough. These things take place in so many parts of the country. We have set up Commissions of Inquiry against politicians who indulged in such practices. That does not mean that article 370 is bad.

Article 370 is an arrangement between the Government of India and the Government of Jammu and Kashmir. Maharajas accession was only on four subjects which was not sufficient. If article 370 is annulled, we are left with the Maharaja's accession with four subjects. Article 370, on the other hand, enables the Government of India to extend laws enacted by the Parliament of India to the State of Jammu and Kashmir with the consent of the Government of Jammu and Kashmir.

Mr. Jagmohan may kindly see how many laws he has extended to Jammu and Kashmir when he was the Governor of Jammu and Kashmir. Now, therefore, to say that article 370 which is the basis of our relationship with India should be annulled, should not be retained or that the position which obtained before article 370, under which certain laws were extended to Jammu and Kashmir should be restored, after reviewing which of them should remain, and thereby political turmoil should be resolved is not correct.

It has been said that the present condition in Jammu and Kashmir is bad. How it is bad, it is a long story. But the question is Mr. Jagmohan went there once in 1983 as the Governor. He was the man who was responsible for toppling the elected Government. He was the man who was then responsible for bringing in the defectors' Government and what effect it had?

Then, in 1990 when he was again sent by Mr. V. P. Singh against the will of the alliance Government of National Conference and the Congress, it was said that out of 900 million people of India any person may

kindly be sent but not Mr. Jagmohan, the reason being what he had done in 1983 to an elected Government. Yet, Mr. V. P. Singh sent him. The Government had made it clear that it would resign if this gentleman comes and they resigned. Mr. Jagmohan then sent a counter-blast. He dissolved the Assembly and keep it under sus- for the State? He did no service. Now, it is not possible to have an Assembly there.

After Mr. Jagmohan took over, it is then that the Pandits migrated in large numbers. There was no migration till then. After he went out from there was no migration. So long as he remained he created migration. He persuaded the people to migrate. That was an anti-national act on his part. Those people have been suffering for that reason. It is to be understood that there are now thousands of Kashmiri pandits living in Jammu and Kashmir. They are living in the Valley of Kashmir. But they are not harmed. Muslims may be harmed by those terrorists. They don't harm those pandits, those Sikhs, those Christians who are living in the Valley of Kashmir and have not migrated. Then let us also see the things which are true. It is true that it is only after Mr. Jagmohan too wrong actions in Jammu and Kashmir that young people opted to run away from their home and that gave grist to the mills of Pakistan. And there were busloads of people lined on the roads who said, "Uri Chalo, Uri Chalo". Mr. Jagmohan was approached. He was told, "You stop them. These young men do not know." But he said, "They are bad elements. Let them go." And they went. Those young boys were enticed by Pakistan across the cease-fire line, trained and sent to us. Now we are in trouble. Are these policies going to save us? I have said repeatedly that we should deal with the Kashmir question with care and caution. We should see that no excess takes place. We should see that of those people who are inside the jail, such of them as are innocent, as the hon. Home Minister had said, are let off. That will be a good step. We have said that those people who have suffered, irrespective of caste, colour or religion, in Jamu and Kashmir, should be compensated. We have said that that you should either revive the Assembly and keep it under suspended animation or change the present set-up. It has become very much corrupt. Have people with political and social background, social service background, in Jammu and Kashmir so that things can be set right.

Now, they are talking of three regions of Jammu and Kashmir. No doubt there are three regions of Jammu and Kashmir. In each region, there is a considerable population of different religions. Jammu province has a 40 per cent Muslim population as three districts are Muslim majority districts. Ladakh, of which they claim to be the sole owners, has the Kargil District with Muslim population. Under the circumstances, what should be done? They say that there should be boards for development. Already there are Distritc Development Boards. These are small matters. Division of the money or assistance we get from the Government of India is a small matter as compared to the great problem which we are facing there. It is said that 90 per cent grant has to be given to the State of Jammu and Kashmir. Is it not true that that grant was never given?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Salaria, please conclude now.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Ultimately, it was during the period of Mr. Chandra Shekhar's Government that that decision was taken to release this 90 per cent to the people of Jammu and Kashmir.

Again, it was recommended repeatedly that the Scheduled Tribes of Jammu and Kashmir should be declared as Scheduled Tribes. That was

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

pending here. No Government took action.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude now. Otherwise, I will call the next speaker.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: I am finishing. Ultimately, the Governor took atcion on it. What credit should have gone to Government at the Centre or the Congress has been taken by the Government there. It is of no use. These things were not done at the proper time.

With these submissions, I say that the allocation is not sufficient, it should have been more and the 90 per cent grant to which we are entitled in Jammu and Kashmir should also be released, for the period for which it was not released.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Prof. Sourendra Bhattacharjee. Not present. Shrimati Bijoya Chakravarty. Not present. Shri Ahluwalia.

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया] : उपसभाध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर के बारे में, उनके बजट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं । एक टूरिस्ट स्टेट के लिए वैसे तो यह बहुत अच्छा साल था जब हम टूरिष्ट इंडिया 1991 का पालन कर रहे थे । काश्मीर भारतवासियों के लिए एक गर्व की जगह है । फिरदोसी ने भी लिखा है —

"गर फिरदोस जमीं अस्त, हमीं अस्त, हमीं अस्त"

अगर स्वर्ग कहीं है, तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है । उस कश्मीर को जलता हुआ देखकर, हम भारतवासियों के दिल और दिमाग में चोट पहुंचती है ।

कुछ क्षण पहले हमारे एक माननीय सदस्य जो अपने आपको कुछ स्टेटों का एक्सपर्ट समझते हैं और अपनी किताब की कालत कर रहे थे, वे बता रहे थे कि किस तरह जम्मू एण्ड काश्मीर का पर कैपिटा एक्सपेंडीचर हाई है और किस तरह दूसरे स्टेटों के साथ है इसका ब्यौरा दे रहे थे । अगर वे उपस्थित होते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि मैं उनको बता सकता कि इस ब्यौरे के साथ क्या क्या जुड़ा रहता है, जैसे उस इलाके की पापुलेशन, उस इलाके की उत्पादकता क्षमता । उनके पहले एक माननीय सदस्या कह रही थीं कि वहां काश्मीर वैली में उत्पादक शक्ति नहीं है, वहां एक ही फसल होती है । वहां एक ही फसल होती है और वहां एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लगा दी गई और यह कह रहे थे कि यहां पर पर-कैपिटा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है अर्थात् यहां उत्पादक व्यवस्था है ही नहीं । वहां अगर पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसकी आप तुलना बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से या आन्ध्र प्रदेश से करने जा रहे हैं, तो वह किस स्तर पर कर रहे हैं, यह सोचने की जरुरत है । वहां पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट इसलिए हाई है कि वहां पर कुछ करने को ही नहीं है टूरिज्म छोड़ कर और सिवाय एक फसल फ्रट को छोड़कर और क्या है ? यह है कि वह हमारे लिए हमारा मादरे वतन का एक हिस्सा है और हमारे लिए गर्व का कारण है कि काश्मीर हमारी मातृभूमि का हिस्सा है । पोस्टरों का और झंडों का बयान किया उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, क्यों नहीं बयान करते उस वक्त कि अगर कहीं पाकिस्तानी झंडे उठते हैं तो उसके जवाब में तिरंगे झंडे दिखाने चाहिएं । भूल गए उस वक्त, जिस वक्त शिव सेना और बजरंग ब्रिगेड के लोगों ने औरंगाबाद के स्टेडियम पर भगवे झंडे चढ़ाए थे । वह इसलिए चढ़ाए कि काश्मीर के स्टेडियम पर पाकिस्तानी झंडा चढ़ा दिया है । वहां पर उन्होंने तिरंगे झंडे को उतार कर भगवा झंडा चढ़ा दिया। उसका विरोध क्यों नहीं हुआ ? तिरंगे झंडे का भी अपमान भगवे झंडे से किया गया । भगवा झंडा इंपार्टेंट है, तिरंगा झंडा उतना इंपार्टेंट नहीं है । उपसभाध्यक्ष महोदय, इनकी मानसिकता, इनकी चिंतन धारा, इनकी सोच, इनकी आइडियोलोजी तो बड़ी साफ है, हिन्दुस्तान में एक बड़ा

मामला था जहां माइनारिटी के लिए काफी हम भी जुड़े हुए हैं, पर यह उस टाईम दिल्ली में डी०डी०ए० के वाइस चेयरमैन थे । तुर्कमान गेट का इतिहास सारा हिन्दुस्तान जानता है । तुर्कमान गेट पर सारा डिमोलिशन इन्होंने करवाया । यही नहीं, अभी जब यह कह रहे थे कि एक छोटी सी जगह दो हजार रुपये की रेंट पर लीज दी गई 99 ईयरज और कितने करोड़ का फायदा ले लिया । जब यह डी०डी०ए० के वाइस चेयरमैन के उस वक्त यहां पर अढ़ाई स्टोरी की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती थी । उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सब जानना जरुरी है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Don't talk about individuals. You can talk on Kashmir. You should not talk about individuals.

SHRI S. S. AHLUWALIA: This is not enough. उपसभाध्यक्ष महोदय, यह इस हाउस को डिस-इन्फर्मेशन है । जिस आदमी ने डिसइन्फर्मेशन दी है इतिहास के पन्नों में उसके बारे में जानना बहुत जरुरी है * दो-दो बार काश्मीर के गवर्नर बने ।... (**व्यवधान**) दो-दो बार काश्मीर के गवर्नर बने और प्लानिंग कमीशन से बैठ कर जम्मू-काश्मीर का प्लान डिसकस किया, वह उस वक्त क्यों नहीं... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is not in good taste. If it is an individual attack, then nothing will go on record. You must restrict yourself to the subject. You can attack his speech. (*Interruptions*)

[**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया**] : उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह गवर्नर थे वहां यह माइग्रेशन हुआ।* जब तीन मुसलमान लड़के इनको सुबह के दरबार में मिले और उन्होंने जाकर रोना-पीटना किया, * * * उन्होंने जाकर रोने-पीटने के बहाने बनाकर बताया कि मैं फलाना गंजू हूं और मैं फलाना मट्टू हूं । अपने को **ब्राह्मण** बताकर इनसे जाकर मिले और इनको कहा कि बड़ा अत्याचार हो रहा है । हमारी बहू-बेटियों को उठाकर मुसलमान ले जा रहे हैं । उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम हमें मिलो । बोले आपका सेक्रेटरी नहीं मिलने देता है । इन्होंने अपना पर्सनल टेलीफोन नम्बर दिया और कहा कि उस टेलीफोन नंबर पर मेरे से संपर्क स्थापित रखो । हम तुम्हें पूरी मदद करेंगे । फिर जब उस लड़के ने रात को कहा कि आज तक जो लोगों का प्रचार था मैं उस पर विश्वास नहीं करता था, पर आज जब अपनी चश्मदीद होकर मैं अपनी आंखों और कानों से देखकर और सुन कर आया हूं ।

9.00 p.m. मेरा नाम वह नहीं था जो मैं बोलने आया था । मेरा नाम फलां है और मैं तुम्हें 24 घंटें के अंदर इसका पाठ सिखाऊंगा और इन्होंने भागकर जम्मू छावनी में अपना अड्डा बना लिया और वहां अपना राजभवन छोड़ दिया । * यह वही पहल है, यह उसी पार्टी की पहल है । ये वैसे तो राष्ट्रपति जी के मनोनीत सदस्य हैं, पर ये उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने पंजाब के टुकड़े करवाए हैं । ये वही पहल थी कि पंजाब में भी इसी तरह से भाषा के नाम पर कहा था कि पटवारी जी, मेरा पुत्तर कह गया है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है । हिंदी और पंजाबी में बिदकारा डालकर जिस तरह से पंजाब के टुकड़े-टुकड़े किए गए उसी तरह आज जम्मू औ काश्मीर के बीच में एक दरार खींचने की कोशिश की जा रही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर इस मुल्क को एक रखना है, अगर इस मुल्क को वाकयी भारत माता का स्वरूप रखना है, जो उसकी गर्दन काश्मीर है, उसी गर्दन को नहीं काटना है तो ऐसे फिरकापरस्त लोगों को दूर रखना पड़ेगा जो इस सत्ता में किसी-न किसी तरह से भागीदार बन जाते हैं, किसी-न-किसी रास्ते से प्रवेश कर लेते हैं और विषाक्तमय वातावरण बनाकर इस देश को अग्निकुंड में डालने की कोशिश

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया]

कर रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर काश्मीर की रक्षा करनी है तो ऐसे भाषण "धारा 370 हटा दो" ऐसे भाषण "उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी सुरक्षा हम ही कर सकते हैं" इनसे देश को बचाकर रखना पड़ेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि काश्मीर में जल्दी-से-जल्दी वहां की पीपुल्स गवर्नमेंट बहाल करने की कोशिश की जाय, वहां की जनता चुनकर अपने चुनिंदे लोगों को एसेंबली में बिठा सके और अगले साल हमें जम्मू काश्मीर का बजट पास न करना पड़े, काश्मीर अपना बजट खुद पास कर सके, ऐसे अधिकार हम उनको दिला सकें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Hon. Vice-Chairman Sir, I am thankful to all Members who had participated in this discusion. They had made very good points. The problem of Jammu and Kashmir is that militancy has badly disrupted normal life and developmental activities undertaken by the Government in Jammu and Kashmir. Sir, it is the endeavour of the Government to combat ignorance, superstition, fanaticism, racialism and economic backwardness and the Government wants to foster brotherhood, equality in communities and make Jammu and Kashmir a true secular State. Sir, there is perpetual law and order problem and ther are terrorist activities in Jammu and Kashmir. There is a political vacuum in the Valley. People do not move to other parts of the State such as Leh and Kargil areas. As far as the Plan outlay is concerned, in 1990-91 the Plan outlay was Rs. 650 crores. In 1991-92 it is Rs. 723 crores. There is an increase of 11 per cent. Government has come forward with a liberal pattern of financial assistance. Sir, the National Development Council has recommended and the Government has agreed that the Central assistance now would be 90 per cent and 10 per cent would be loan. Jammu and Kashmir State is a chronically deficit State. Expenditure on account of servicing loans is very high. Expenditure on paramilitary forces, additional police and battalions is also on the increase on account of the terrorist activities. There is the rehabilitation programme. Then there is the acceptance of the Fourth Pay Comimssion's recommendations and release of DA instalments to the tune of Rs. 32 crores. Due to the law and order situation tourism, transport, industry and power generation have suffered. In spite of these setbacks, agriculture, handicrafts and horticulture are doing well. Ninety per cent of the villages in Jammu and Kashmir are electrified.

Questions have been asked about the migrants. The total number of registered migrants from Jammu and Kashmir is 72,000 families. Of these 50,000 are residing in Jammu and 14,000 in Delhi. In Jammu they are residing in camps managed by the State Government. In Jammu the migrants are provided a maximum of Rs. 1,000 per month per family and free rations and free camp accommodation. In New Delhi also the migrants are provided with free rations, free camp accommodation and a cash allowance of Rs. 500 per migrant family. Those who are not residing in the camps are given Rs. 800 per month. At present there are 40,000 in Jammu and 18,000 in Delhi. They largely consist of Hindus and Sikhs. The relief assistance provided to the migrants is the best given anywhere in India and endeavour is being made to provide good basic civic amenities to the migrants in the camps.

Some honourable Members have asked about the provision for law and order and security and for rehabilitation in the Budget. Insofar as relief and rehabilitation and welfare of migrants is concerned, an amount of Rs. 55 crores has been provided in the current year's Budget. Cash assistance to the migrants is Rs. 36 crores. Free rations to the migrants, Rs. 11 crores, amenities and other

provisions for migrants Rs. 8 crores. In regard to security and law and order a provision of Rs. 80 crores has been made in the current year's Budget.

A question has been asked alleging discrimination between Jammu and Kashmir regions. There is no discrimination whatsoever made in the Budget proposals between Jammu region on the one hand, and Kashmir valley on the other. In fact, the Government of India is committed to removal of regional imbalances and the Budget provisions have been made keeping that in view. Besides these two regions the State also consists of Ladakh region which is also receiving due attention of the Government.

With these words, Sir, I request this honourable House to take the Bill into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The question is:

"That the Bill to authorise payment and and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Sir I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JAGESH DESAI: Sir, I would like to make a suggestion. Before we take up the second Bill, we would like the Prime Minister to make his statement on the five diamond merchant who were kidnapped. We are anxious to know as to what has happened.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): No, let us pass the Bill first.... *(Interruptions)*

SHRI VIREN J. SHAH: Let us finish the legislative business first.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The consensus of the House is that the Bill should be taken up first.

THE ELECTRICITY LAWS (AMENDMENT, BILL, 1991

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

विद्युत की लगातार मांग और संसाधनों की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा इस क्षेत्र में अपना समुचित योगदान दिए जाने को ध्यान में रखते हुए विद्युत में निजी क्षेत्र निवेश को तत्साहित कए जाने के माध्य से विद्युत उत्प दन सप्लाई एवं वितरण क्षम। संवर्धन किए जाने संबंधी कार्यक्रम हेतु संसाधनों में बढ़ोत्तरी किये जाने संबंध नीति के बारे में सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से विचार किया जाता रहा है जून, 1988 में, तत्कालीन सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इस समय, कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में निजी क्षेत्र का केवल 4 प्रतिशत का योगदान है। यद्यपि विद्युत की सप्लाई एवं वितरण हेतु 57 वितरण कम्पनियों को लाइसें दिया गया है, तथापि अब तक नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र के विद्यमान लाइसेंसधारियों को केवल क्षमता-संवर्द्धन और क्षमता-प्रतिस्थापन हु अनमति दी जाती रही है। संसाधनोंमें